घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 132- रविवार 15- मार्च 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सिलचर में 23,550 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

कांग्रेस ने असम के युवाओं को गुमराह किया बीजेपी ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले : मोदी

गुवाहाटी,14 मार्च 2026। पीएम मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम के युवाओं को गुमराह किया। उन्हें हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला। लेकिन आज यह राज्य अवसरों का सागर है। पीएम ने बताया कि कांग्रेस ने असम को 'फूट डालो-राज करो' नीति में रखा। आज असम खुला आसमान है। असम भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर का अहम हिस्सा बन रहा है। राज्य ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले हैं। पीएम अपनी स्पीच में कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने इसे ऐसे कनेक्ट किया जिसकी हर जगह चर्चा है। नॉर्थ ईस्ट आज दक्षिण एशिया जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। इसके पहले मोदी ने सिलचर में 23,550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिचलर को बराक घाटी का गेटवे है। लेकिन कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दूर रखा था।

पीएम ने कहा...कांग्रेस ने झूठी रील बनाने की इंडस्ट्री खोली,युवा सतर्क रहें...

कांग्रेस मोदी को भर-भर के गाली दे। कांग्रेस का देश के लिए कोई विजन नहीं है। इन्होंने झूठी रील बनाने की इंडस्ट्री खोली हुई है। दुनिया भारत के तेज विकास को नहीं पचा पा रही है। कांग्रेस विदेश ताकतों के हाथ की कठपुलती रहेगी। असम के हर नागरिक को, हर नौजवान को कांग्रेस से सर्तक रहना है। अमस, बराक वैली विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। वह दिन दूर नहीं, जब बराक वैली को विकास के नए सेंटर के रूप में पहचान मिलेगी।

कांग्रेस की कोशिश पैनिक क्रिएट हो और देश मुश्किल में फंसे : पीएम मोदी

मोदी ने अपने संबोधन में कहा- पूरे देश ने कांग्रेस के इस कपड़ा फाड़ भद्दे प्रदर्शन की बुराई की। दिल्ली का परिवार इसे अपना मेडल मान रहा है। दुनिया में चारों तरफ, हमारे पड़ोस में युद्ध के हालात हैं। इसके कारण बनी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों के लिए कम से कम मुसीबतें आए,सरकार उसके लिए प्रयास कर रही हैं। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वह जिम्मेदार रानजीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन वह एक बार फिर फेल हो गई।

मोदी बोले- आज असम खुला आसमान है, राज्य ने सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले

मोदी ने कहा- असम सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए रास्ते खोले, युवाओं को स्कॉलरशिप जी, उनके लिए नए रास्ते खोली। बीजेपी के शिक्षा,कौशल विकास, स्वास्थय सेवा बड़ी जिम्मेदारी रही हैं। असम ने पहले इनके लिए बहुत कुछ झेला है। आज असम इन सब सेवाओं का बड़ा हब बनकर सामने आ रहा है। कांग्रेस ने असम को फूट डालो, राज करो नीति में रखा।

पीएम ने कहा...विकास की दौड़ में पीछे रहने वालों को बीजेपी प्राथमकिता देती है

जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया,भाजपा उसे प्राथमिकता देती है। कांग्रेस की सरकार बॉर्डर एरिया को अंतिम गांव मानती थी। हम इन्हें पहला गांव मानते हैं। बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले बाइब्रेंट विलेज का यहां से शुरूआत की। यहां चाय बागानों में काम करने वाले हजारों परिवारों को उनकी जमीन देने का ऐतिहासिक काम किया है। यह बड़ी शुरूआत है। इससे इन परिवारों को सुरक्षा, सम्मान मिला है।

मोदी ने कहा...असम के विकास में किसानों का योगदान

असम की डबल इंजन की सरकार असम के विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। गुवाहाटी में मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की। 30 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। यहां के किसानों, चाय बागानों के श्रमिकों का असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20 हजार करोड़ दिया है। कांग्रेस ने यहां 10 साल राज किया, एक फूटी कौड़ी असम को नहीं दी। बराक वैली के किसानों के खातों में भी यह वाली किस्त पहुंची है। चुनाव के बाद भी यह किस्त पहुंचेगी। यह पैसा खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। बराक वैली अब अपनी फसलों के लिए ही नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च के लिए जानी जाएगी। यहां पर पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण आज से शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को दी 18,680 करोड़ की सड़क,रेल और पोर्ट परियोजनाओं की सौगात

बंगाल की निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा : पीएम मोदी

कोलकाता,14 मार्च 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल को 18,680 करोड़ की सड़क,रेल और बंदरगाह से जुड़ी बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं को राज्य में आधारभूत ढांचे के विस्तार,औद्योगिक विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब राज्य के लोगों के दिलों में यह बात छप चुकी है कि बंगाल की 'निर्मम सरकार' का अंत होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव का माहौल बन चुका है और इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत बंगाली भाषा में लोगों का अभिवादन करते हुए की। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 'प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उमड़ी विशाल भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आज बंगाल क्या सोच रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह और जोश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य में परिवर्तन की इच्छा मजबूत हो चुकी है। मोदी ने कहा कि ब्रिगेड मैदान का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब-जब बंगाल ने देश को दिशा दी है,तब-तब यह मैदान बंगाल की आवाज बना है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ इसी मैदान से उठी आवाज पूरे देश में क्रांति बन गई थी और अंततः अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का अंत हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक बार फिर इसी मैदान से 'नए बंगाल की क्रांति' का बिगुल बज चुका है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और लोगों के दिलों में भी दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल से 'महाजंगलराज' का खात्मा होगा और राज्य में कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के हर कोने से आवाज उठ रही है- 'चाई बीजेपी सरकार, अबकी बार। ' प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने रैली में आने वाले लोगों को 'चोर' कहकर अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि असली चोर कौन है, यह बंगाल की जागरूक जनता अच्छी तरह जानती है। मोदी ने कहा कि अपनी सत्ता जाते हुए देखकर राज्य की सरकार बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम कोशिशों के बावजूद टीएमसी सरकार लोगों को इस रैली में शामिल होने से नहीं रोक पाई।

कांग्रेस की नीतियों के कारण बसपा का गठन करना पड़ा : मायावती

लखनऊ,14 मार्च 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्मंत्री मायावती ने कहा कि यदि कांग्रेस बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और कांशीराम के मिशन के प्रति समर्पित होकर संविधान के पवित्र समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्य को जमीन पर उतारने का कार्य अगर सही नीयत व नीति से करती तो कांशीराम जी को कभी बसपा की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती। बसपा प्रमुख ने शनिवार को एक बयान में कहा कि केंद्र की सत्ता में काफी समय रहते हुए कांग्रेस ने डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। कांशीराम के निधन पर तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शोक व सपा सरकार ने एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इसके अलावा इन महापुरुषों के नाम बनाए गए शिक्षण,मेडिकल संस्थानों व जिलों के नाम भी बदले गए। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के संबंधी के बिल को संसद में क्यो फाड़ा गया ? बसपा प्रमुख ने कहा कि इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल कर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। अब ये सभी पार्टियां आए दिन किस्म- किस्म के हथकण्डे इस्तेमाल करके बसपा को कमजोर करने में लगी हैं।

लातेहार में इनामी नक्सली कमांडर मृत्युंजय भुइया समेत दो माओवादी गिरफ्तार,एके-47 और कारतूस बरामद

लातेहार,14 मार्च 2026। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के दो इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सलियों में जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइया और सब-जोनल कमांडर बबलू राम शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक स्वचालित एके-47 रायफल, 21 जिंदा कारतूस और लेवी के लगभग 1.60 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। दरअसल, लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी संगठन का जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइया अपने दस्ते के साथ छिपादोहर थाना क्षेत्र के हरिणामाड़ गांव के आसपास आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में छापेमारी अभियान चलाया और गांव के पास घेराबंदी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली मृत्युंजय भुइया छिपादोहर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव का रहने वाला है और वह माओवादी संगठन में जोनल कमांडर के पद पर कार्यरत था। उस पर झारखंड पुलिस ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं उसके साथ पकड़ा गया बबलू राम बिहार के अरवल जिले के निरखपुर गांव का निवासी है और माओवादी संगठन में सब-जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय था।

एमएसपी और किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर केंद्र सरकार पर किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2021 में किसानों से सी2+50 प्रतिशत के आधार पर कानूनी एमएसपी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लोकसभा में पूछे गए प्रश्न को साझा करते हुए सरकार से पूछा था कि क्या सरकार ने 2021 में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से यह वादा किया था कि सभी फसलों के लिए विधिक गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा? उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सरकार द्वारा इसे लागू न कर पाने के क्या कारण हैं? साथ ही सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने देश में उत्पादन घाटे का सामना कर रही कुछ दालों और तिलहन जैसी फसलों की सीधी खरीद पर विचार किया है।

सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्युरिटी एक्ट हटाया

170 दिन बाद जोधपुर जेल से रिहा,लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। केंद्र ने शनिवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्युरिटी एक्ट हटा दिया। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, सोनम नेशनल सिक्युरिटी एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे सोनम की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंचीं। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। फिर दोपहर सवा एक बजे पत्नी के साथ एक निजी गाड़ी से जेल से निकले। दरअसल, सोनम के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमके तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में हैं। अब उनकी रिहाई होगी। नेशनल सिक्युरिटी एक्ट सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।

दो दिन पहले वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था : लद्दाख के लिए ईमानदार संवाद आवश्यक है। मैंने एक्टिविज्म से दूरी नहीं बनाई है। लद्दाख के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले जैसी ही है। इसका उद्देश्य लद्दाख के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी भविष्य है। 4 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें लद्दाख के दो प्रमुख संगठन लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेट्स अलायंस शामिल हुए। इनके नेताओं ने वांगचुक की रिहाई की मांग दोहराई थी। सोनम को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। वह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी।

सरकार बोली...बातचीत का माहौल बनाने लिए फैसला लिया

सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की याचिका पर अंतिम सुनवाई (17 मार्च) के दो दिन पहले लिया। कोर्ट सुनवाई के दौरान वे वीडियो और फोटो देखेगा, जिनके आधार पर सरकार ने उन परनेशनल सिक्युरिटी एक्ट लगाया था। केंद्र सरकार ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिए लिया गया है। लद्दाख में विभिन्न समुदायों और नेताओं के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का असर छात्रों, नौकरी चाहने वालों, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए हाई-पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत जारी रहेगी।

अगले दो दिनों में 92 हजार टन गैस लेकर दो जहाज पहुंचेंगे भारत

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। देश में घरेलू रसोई गैस आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए दो भारतीय जहाज जल्द ही गुजरात के बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं। इनमें कुल 92,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लदी हुई है और ये 16-17 मार्च को गुजरात के प्रमुख पोर्ट्स पर डॉक करेंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार इन जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर बंदरगाह पर लगाने की व्यवस्था की गई है ताकि गैस आपूर्ति प्रभावित न हो। इससे रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने और संभावित संकट को कम करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि महानिदेशालय नौवहन भारतीय ध्वज वाले जहाजों और उन पर तैनात भारतीय नाविकों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। इसके लिए जहाज मालिकों,आरपीएसएन एजेंसियों और भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में पोत परिवहन के कंट्रोल रूप में पिछले 24 घंटों में 312 फोन कॉल और 460 ई-मेल प्राप्त हुए हैं। ये संदेश नाविकों, उनके परिजनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हैं। सभी कॉल और इमेल के जवाब दिए गए है। कुल मिलाकर अब तक 5000 कॉल और 5000 ई-मेल के जवाब दिए गए हैं। सिन्हा ने बताया कि फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में 24 भारतीय-ध्वज वाले जहाज़ मौजूद थे। इनमें से दो जहाज़– शिवालिक और नंदा देवी जो दोनों एलपीजी कैरियर है, आज तड़के सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों में लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है।

असम के कार्बी आंगलोंग में बस पेड़ से टकराई

चालक समेत चार लोगों की मौत,10 घायल

असम,14 मार्च 2026। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में शनिवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में चालक सहित चार लोगों की मौत हो गई,जबकि 10 अन्य यात्री घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक यात्री बस अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। पुलिस के अनुसार,दुर्घटना लक्खीजान इलाके में हुई, जो बोकाजान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बस मोइराबाड़ी (जिला मोरीगांव जिला) से डिमापुर की ओर जा रही थी। सभी एक मोड़ पर मुड़ते समय चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक सहित चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अब्दुल बारेक, खलील रहमान, शबीना सुल्ताना और अलाउद्दीन के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

अकासा एयर 15 मार्च से लगाएगा फ्यूल सरचार्ज टिकट होंगे महंगे..

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयर ने भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। यह सरचार्ज 199 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक होगा, जो 15 मार्च से लागू होगा और उड़ान की अवधि के आधार पर लगेगा। अकासा एयर ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वह अपने हर उड़ान पर सरचार्ज लगाएगी आकासा एयर के मुताबिक एयरलाइन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर 15 मार्च को 00:01 बजे से की गई सभी बुकिंग पर 199 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लगाएगी।

पंजाब में भाजपा अकेले बनाएगी अगली सरकार

नशा-कर्ज-धर्म परिवर्तन पर बीजेपी ही समाधान : शाह

चंडीगढ़,14 मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में भाजपा का चुनावी शंखनाद करते हुए साफ कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी और सरकार बनाएगी। शनिवार को मोगा के गांव किल्ली चाहलां में भाजपा की पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब तक भाजपा पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि पार्टी खुद सरकार बनाए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता आज भाजपा के साथ है। पंजाब के ज्वलंत नशों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस व अकाली दल ने पंजाब में नशों को बढ़ावा दिया है। चार महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का दावा करने वाला आम आदमी पार्टी भी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाई। पंजाब को केवल भाजपा ही नशा मुक्त राज्य बना सकती है। भाजपा ने वादे के अनुसार,कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या कर्ज, ड्रग्स, धर्म परिवर्तन,भ्रष्टाचार, गैंगस्टरवाद है। आज पंजाब से उद्योग पलायन कर रहे हैं। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। युवाओं के पास अपने भविष्य को लेकर कोई विजन नहीं है। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में 19 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड में जब 19 प्रतिशत वोट मिले तो अगली सरकार भाजपा ने बनाई। इस बार पंजाब में सरकार बनाने का समय आ गया है। पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा कि पंजाब में आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू,पैनिक बुकिंग से बचें : पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देशभर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। वहीं, घरेलू रसोई गैस की सप्लाई में भी तेजी से सुधार हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। इसके पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन लोग अभी भी बड़े पैमाने पर पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पैनिक बुकिंग से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 'शिवालिक' और 'नंदा' नाम के हमारे एलपीजी टैंकर इस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज पास को पार कर चुके हैं और भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बड़ा ऊर्जा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है, क्योंकि ये दोनों पोत कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन गैस का बड़ा शिपमेंट लेकर आ रहे हैं। शर्मा ने कहा...कमर्शियल गैस सिलेंडरों के बारे में काफी चर्चा हुई है उसके बाद निर्णय यह लिया गया कि व्यावसायिक उपभोक्ता को कुछ एलपीजी दी जाए। इस संबंध में राज्य सरकार से भी बात हुई है...और 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यावसायिक सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया है और वो ग्राहक को मिल रहे है...। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) ने कहा, जहां तक कच्चे तेल और रिफाइनरियों का सवाल है, हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति है, और हमारी रिफाइनरी भी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। खुदरा दुकानों पर स्टॉक खत्म होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। पेट्रोल-डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करते हैं,इसलिए हमें आयात करने की कोई जरूरत नहीं है।

संपादकीय

अनिद्रा की महामारी

भारतीय जन-जीवन में तेजी से घर करती डिजिटल जीवन शैली ने युवाओं की नींद को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिसके चलते उनमें आक्रामकता, अवसाद व आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। देश-दुनिया में समय-समय पर आने वाले विभिन्न सर्वेक्षण इस संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन देश में किशोरों का स्क्रीन टाइम घातक ढंग से बढ़ रहा है। आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं कि किशोरों की सेहत के लिये आठ घंटे की नींद जरूरी होती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ आठ घंटे के बजाय सात-छह घंटे की नींद को भी पर्याप्त मानते हैं,बशर्ते उसमें बीच में किसी तरह का व्यवधान न हो। लेकिन बिना किसी जरूरी काम के कथित सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना आज के दौर में फैशन सा बन गया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में हुए हालिया शोध बताते हैं कि रात में जल्दी सोने व सुबह जल्दी उठने से बेहतर स्वास्थ्य बनता है। यह भारतीय जीवन दर्शन की अपरिहार्य धारणा भी रही है। लेकिन देश में पहले टीवी और अब मोबाइल फोन के अनियंत्रित उपयोग ने युवाओं की रात की नींद उड़ा दी है। जिसके चलते युवा पूरे दिन उखड़े-उखड़े और अशांत रहते हैं। उनमें आक्रामकता बढ़ रही है। फिर वे अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बाधित नींद की इस स्थिति में कालांतर मन में आत्महत्या जैसे नकारात्मक भाव उमड़ने लगते हैं। एक सर्वे बताता है कि देश में 73 फीसदी दसवीं के छात्र आठ घंटे से कम की नींद सोते हैं। कलकत्ता स्लीप सोसाइटी के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया में 60 से 70 फीसदी किशोर पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल, आज छात्रों पर अभिभावकों व शिक्षकों का अनुशासन कम ही चलता है। मां-बाप के टोकने पर वे दलील देते हैं कि ऑन लाइन पढ़ाई चल रही है। कोरोना संकट ने देश-दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प तो दिया, लेकिन तमाम तरह की विसंगतियां व विकृतियां भी किशोरों के जीवन में भर दी हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है कि देश में सत्तर करोड़ भारतीय छह घंटे की नींद नहीं ले पाते। वहीं 46 प्रतिशत भारतीय छह घंटे से कम की नींद ले पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट युवाओं व किशोरों से जुड़ा है। वे देर रात तक ऑनलाइन गेमों से जुड़े रहते हैं। रात में जाने-अनजाने दोस्त उनके सहभागी बनते हैं। जो कालांतर एक नशे की लत का रूप ले लेता है। परिजनों की रोक-टोक उन्हें रास नहीं आती। कई घटनाओं में उनके आक्रामक व्यवहार के घातक परिणाम सामने आए हैं। यहां तक कि नजदीकी परिजनों की हत्या की घटनाएं भी हुई हैं। दरअसल,ऑनलाइन खेलों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे किशोरों के लिये नशा बन जाते हैं। रात का एकांत उन्हें रास आता है। जिसके चलते वे नींद की परवाह नहीं करते। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया व ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर तमाम वर्जित व अश्लील सामग्री की रात्रि में भरमार रहती है। जिसकी चपेट में छोटे-बड़े लोग आ रहे हैं। युवा देर रात का एकांत तलाशते हैं ताकि परिजनों की अनुपस्थिति में वे मनमानी कर सकें। वे देर रात तक ऑनलाइन रहने में अपनी शान समझते हैं। यह भूल जाते हैं कि वास्तव में, वे अपनी सेहत से किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ चेतावनी देते रहे हैं अनिद्रा से उच्च रक्तचाप की समस्या पैदा हो रही है। जो कालांतर हाइपरटेंशन में बदल जाती है। दरअसल,शरीर की जैविक घड़ी के परिचालन में व्यवधान से शरीर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। देर रात जागने और मोबाइल के नशे में किशोर असमय खाते-पीते हैं, जिससे उनमें मोटापे की समस्या भी घर कर रही है। यही वजह है कि अब किशोरों तक में डाइबिटीज की समस्या देखने में आ रही है। दरअसल, कुदरती सोने के समय का विकल्प देर रात या सुबह की नींद नहीं हो सकती है। यह संकट बड़ा है और अभिभावकों व शिक्षकों को किशोरों की देर रात जागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये गंभीर प्रयास करने होंगे। अन्यथा देश को कालांतर अस्वस्थ युवा पीढ़ी का संत्रास झेलने को बाध्य होना पड़ेगा।

जीवन की सफर में

सबके जिंदगी की सफर सहज है
देखने मे लगता यह कोई महज? है।।

कदम कदम पर बाधा खड़ा
काट देना प्रभु तुमसे अरज है।।

लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना
आप से मेरा यह एक अरज है।।

जीवन में कई दायित्व मिलेगा
इसे निभाना तुमसे एक अरज है।।

अपने पराये मे अंतर ना रखना
समान समझना तुम से अरज है।।

मानवता की भाव तू सजाए रखना
दानव ना बनना तुमसे यही अरज है।।

नि:स्वार्थ भाव लिए काज करना
परोपकारी बनना तुमसे यह अरज है।।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेष....

जागरूक उपभोक्ता ही है सुरक्षित बाजार की नींव

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी,कालाबाजारी,घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए देश में 20 जुलाई 2020 को 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया,जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान हैं। यह कानून अब साढ़े तीन दशक पुराने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' का स्थान ले चुका है...

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

जमाखोरी,कालाबाजारी, मिलावट,नाप-तोल में गड़बड़ी,मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री,ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना इत्यादि समस्याओं से ग्राहकों का सामना अक्सर होता रहता है। ऐसी ही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 'सुरक्षित उत्पाद,आश्वस्त उपभोक्ता' विषय के साथ मनाया जा रहा है। यह वैश्विक पहल उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता जागरूकता और मजबूत नियमों की आवश्यकता पर जोर देती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्व अवसर है। उपभोक्ता आन्दोलन की नींव सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका में रखी गई थी और 15 मार्च 1983 से यह दिवस इसी दिन निरन्तर मनाया जा रहा है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। वैसे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होना कोई नई बात नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के शोषण की जड़ें आज बहुत गहरी हो चुकी हैं। उपभोक्ताओं को इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून भी बनाए गए लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित एवं कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां व प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं अथवा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रति सचेत हुए।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ताओं का शोषण होने और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। एक उपभोक्ता ने एक दुकान से बिजली का एक पंखा खरीदा लेकिन एक वर्ष की गारंटी होने के बावजूद थोड़े ही समय बाद पंखा खराब होने पर भी जब दुकानदार उसे ठीक कराने या बदलने में आनाकानी करने लगा तो उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने आदेश में नया पंखा देने के साथ उपभोक्ता को हर्जाना देने का भी फरमान सुनाया। एक अन्य मामले में एक आवेदक ने सरकारी नौकरी के लिए अपना आवेदन अंतिम तिथि से पांच दिन पूर्व ही स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित विभाग को भेज दिया लेकिन आवेदन निर्धारित तिथि तक नहीं पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया। आवेदक ने डाक विभाग की लापरवाही को लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे न्याय मिला। चूंकि स्पीड पोस्ट को डाक अधिनियम में एक आवश्यक सेवा माना गया है, इसलिए उपभोक्ता अदालत ने डाक विभाग को सेवा शर्तों में कमी का दोषी पाते हुए डाक विभाग

को मुआवजे के तौर पर आवेदक को एक हजार रुपये की राशि देने का आदेश दिया। ऐसी ही छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना ही पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है लेकिन जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो आश्चर्य होता है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत ही नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढ़ंग से नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत तो पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना ही आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा 36 वर्षों से साहित्य एवं पत्रकारिता में सक्रिय हैं)

क्या बिहार में भाजपा का तीसरा दांव बाकी है

पवन वर्मा

राजनीति में चौंकाने की कला बहुत कम दलों के पास होती है। हाल के महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने यह कला फिर दिखा दी है। पहले बिहार से आने वाले नेता नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और उसके कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार को राज्यसभा की राह दिखाना। ये दोनों फैसले ऐसे रहे, जिन्होंने बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों को भी चौंका दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में भाजपा का तीसरा दांव अभी बाकी है, और वह दांव किस रूप में सामने आएगा? पहले इन दो फैसलों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। भाजपा की राजनीति अक्सर लंबी रणनीति पर आधारित होती है। पार्टी कई बार ऐसे कदम उठाती है जो पहली नजर में अचानक लगते हैं, लेकिन उनके पीछे दूरगामी राजनीतिक गणित छिपा होता है। बिहार के संदर्भ में पिछले चार महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, वे इसी रणनीतिक शैली की ओर संकेत करती हैं। जब नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो यह केवल संगठनात्मक निर्णय नहीं था। राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के एक नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कई संकेतों से भरा हुआ था। पहला संकेत यह था कि भाजपा बिहार को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। दूसरा संकेत यह था कि पार्टी राज्य की राजनीति में नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए तैयार है और तीसरा संकेत यह था कि संगठनात्मक स्तर पर बिहार की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। नितिन नबीन लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। संगठन, सरकार और चुनाव, तीनों स्तरों पर उनका अनुभव रहा है। लेकिन उन्हें सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना एक ऐसा फैसला था जिसकी पहले व्यापक चर्चा नहीं थी। यही कारण है कि यह निर्णय राजनीतिक हलकों में अप्रत्याशित माना गया। अभी पहले फैसले की गूंज पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि दूसरा बड़ा निर्णय सामने आ गया। नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन। बिहार की राजनीति में दो दशकों तक मुख्यमंत्री रहे

नेता का अचानक राज्यसभा की ओर जाना सामान्य घटना नहीं है। यह कदम बिहार की सत्ता संरचना को सीधे प्रभावित करता है। क्योंकि इसके साथ ही यह सवाल खड़ा हो गया कि अब राज्य की कमान किसके हाथ में होगी? नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार की राजनीति का केंद्रीय चेहरा रहे हैं। गठबंधन बदलते रहे, लेकिन सत्ता का संतुलन अक्सर उनके इर्द-गिर्द ही बना रहा। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक युग के अंत और नए दौर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। यदि इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखा जाए तो ये केवल राजनीतिक फैसले लग सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें एक साथ देखा जाए, तो इनके भीतर एक बड़ी रणनीति की झलक मिलती है। पहले बिहार से एक नेता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना और फिर राज्य की सत्ता संरचना में बड़ा परिवर्तन लाना यह क्रम संकेत देता है कि भाजपा बिहार को लेकर दीर्घकालिक राजनीतिक योजना पर काम कर रही है। यह योजना केवल वर्तमान सरकार तक सीमित नहीं हो सकती। इसका संबंध आने वाले चुनावों और उससे आगे की राजनीति से भी हो सकता है। नीतीश कुमार की विदाई के बीच अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र यही है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? इस समय सवाल केवल नाम का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संतुलन का है जो आगे की राजनीति को तय करेगा। मुख्यमंत्री का चयन करते समय कई कारक सामने आते हैं। सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक संतुलन,गठबंधन की मजबूती और चुनावी रणनीति। बिहार की राजनीति में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह पद किस दल के पास जाएगा या किस चेहरे को आगे लाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला साधारण नहीं होगा। यहीं से तीसरा सवाल जन्म लेता है कि क्या मुख्यमंत्री चयन में भी भाजपा कोई ऐसा फैसला ले सकती है जो सबको चौंका दे? भाजपा का हाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि पार्टी कई बार ऐसे चेहरे सामने लाती है जिनकी पहले व्यापक चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश,राजस्थान,उड़ीसा,गुजरात, छत्तीसगढ़ राज्यों में मुख्यमंत्री चयन के समय यह शैली दिखाई दे चुकी है। ऐसे फैसलों के पीछे पार्टी का तर्क होता है कि नया चेहरा संगठन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा और सत्ता संतुलन को नए ढंग से स्थापित कर सकेगा। बिहार में भी यह संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। यदि पार्टी यह मानती है कि राज्य की राजनीति में नया प्रयोग करने का समय है, तो वह अपेक्षित दावेदारों की जगह किसी नए चेहरे को सामने ला सकती है। इस पूरे समीकरण में जनता दल (यूनाइटेड) की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जदयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह नीतीश कुमार के बाद अपनी राजनीतिक पहचान को कैसे बनाए रखे। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई अनुभवी नेता हैं, लेकिन नीतीश के कद का नेतृत्व तैयार करना आसान नहीं होगा। इसलिए जदयू के सामने भी यह चुनौती है कि वह ऐसा चेहरा सामने लाए जो पार्टी को एकजुट रख सके। दूसरी ओर विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। खास तौर पर लालू पुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस स्थिति को राजनीतिक अवसर के रूप में देख सकती है। विपक्ष का प्रयास रहेगा कि इस परिवर्तन को सत्ता की अस्थिरता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि नया मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत कम अनुभव वाला हुआ, तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। बिहार की राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चार महीनों में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना दो ऐसे अप्रत्याशित निर्णय सामने आए हैं जिन्होंने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। अब सबकी नजर भाजपा के तीसरे दांव पर है और वह है मुख्यमंत्री का चेहरा।

कविता

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक (हरियाणा)

कितना इंतजार करती है मां

मां बनने से पहले बहुत सपने पालती है मां
अपनी कोख से बेटी नहीं बेटा चाहती है मां।
9 महीने अपनी कोख में उसे पालती है मां।
बेटे के पैदा होने पर उसे कृष्णा समझती है मां
अपना सब कुछ त्याग कर बेटे को पालती है मां।
प्रत्येक दिन उसके बड़े होने का इंतजार करती है मां
अच्छे संस्कार देकर उसे बड़ा आदमी बनाती है मां।
उसके नाजो नखरे उठाकर बहुत खुश होती है मां
बड़ा होकर बेटा सुख देगा ऐसा सोचती है मां
उसके लिए सुंदर बहू लाकर बहुत खुश होती है मां।
पोते को गोद में खिलाने के सपने देखती है मां
बेटे और बहू से सेवा करवाना चाहती है यह मां।
अब उसकी जिंदगी सुखी हो जाएगी सोचती है मां
बेटा और बहू कनाडा चले जाते हैं नौकरी के लिए
वापस आकर उसकी सेवा करेंगे इंतजार करती है मां।
कनाडा से बेटे की आवाज सुनने का इंतजार करती है मां
कनाडा से कोई फोन नहीं आता रात को सो नहीं पाती मां।
जिस बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया था उसको देखने
के लिए रात दिन इंतजार करती रहती है यह बेचारी मां।
कोई फोन नहीं आता बेटा कोई भी पैसा नहीं भेजता
फिर भी उसकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है मां।
अपनी बीमारी खबर बेदिली से बेटे को भेजती है मां
इंतजार करते-करते बेटे का, आखिर स्वर्ग सिधार जाती है मां
बेटे को देखने के लिए मरने पर भी आंखें खुली रखती है मां।
बेटा पैदा करने के सुख को ता उम्र तरसती रहती है बेचारी मां।

संकट की घड़ी...!

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

जब संकट की घड़ी आती है,
यह 'परख' वहीं पर होती है।
कौन खड़ा यहाँ देश के साथ,
सच्चाई में बढ़े सभी के हाथ।

ये तेल-गैस की कमी हो चाहे,
कहीं ना कहीं से खुलेंगी राहें।
माना अभी कठिन हैं हालात,
यूं धैर्य-हिम्मत रखिए लम्हात।

विपक्षी सवाल उठाएंगे जरूर,
देशहित सबसे ऊपर हैं हुजूर।
पक्ष-विपक्ष समाज आगे आए,
हम हरेक मुश्किल से पार पाएँ।

आईसीसी में 'नो हैंडशेक', आईपीएल में पाकिस्तानी?

सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने अबरार अहमद के पुराने पोस्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। इसके बाद कुछ समूहों ने सनराइजर्स ब्रांड के खिलाफ बहिष्कार की मांग शुरू कर दी और कई हैशटैग चलने लगे। अनेक पोस्टों में टीम प्रबंधन और विशेष रूप से काव्या मारन की आलोचना की गई। इस प्रकार एक खिलाड़ी की खरीद का मामला केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ गया।

डॉ. प्रियंका सौरभ

क्रिकेट लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद संवाद और संपर्क का एक माध्यम माना जाता रहा है। कई अवसरों पर यह खेल कूटनीतिक पुल की तरह भी काम करता रहा है, जिसने राजनीतिक मतभेदों के बीच भी दोनों देशों के लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाई। किंतु हाल के वर्षों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, डिजिटल मीडिया की तीखी प्रतिक्रियाएँ और राष्ट्रवादी भावनाओं की तीव्रता ने इस परंपरा को चुनौती देना शुरू कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड की फ्रेंचाइज़ी लीग द हंड्रेड की 2026 की नीलामी में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स द्वारा खरीदे जाने के बाद एक नया विवाद सामने आया। यह टीम भारतीय आईपीएल फ्रेंचाइज़ी सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी मानी जाती है और इसके साथ काव्या मारन का नाम भी जोड़ा जाता है। खेल की एक सामान्य नीलामी का यह निर्णय देखते ही देखते सोशल मीडिया की बहस,राष्ट्रीय भावना और वैश्विक क्रिकेट की स्वायत्तता से जुड़ी बड़ी चर्चा में बदल गया। मार्च 2026 में आयोजित इस नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को लगभग 1.9 लाख पाउंड में अपनी टीम में शामिल किया। टीम प्रबंधन के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह क्रिकेटीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया गया था। टीम को मध्य ओवरों में विकेट लेने वाले एक विदेशी स्पिनर की आवश्यकता थी,क्योंकि उनके प्रमुख स्पिनर आदिल रशीद किसी अन्य फ्रेंचाइज़ी से जुड़ चुके थे। टीम के कोच डेनियल विट्टोरी ने भी स्पष्ट किया कि चयन कई विकल्पों पर विचार करने के बाद किया गया और अबरार टीम की रणनीति के अनुसार सबसे उपयुक्त खिलाड़ी थे। इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशासनिक निकाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी यह रुख दोहराया कि लीग में खिलाड़ियों का चयन उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रदर्शन और टीम की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। हालांकि यह निर्णय जल्द ही विवाद का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने अबरार अहमद के पुराने पोस्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। इसके बाद कुछ समूहों ने सनराइजर्स ब्रांड के खिलाफ बहिष्कार की मांग शुरू कर दी और कई हैशटैग चलने लगे। अनेक पोस्टों में टीम प्रबंधन और विशेष रूप से काव्या मारन की आलोचना की गई। इस प्रकार एक खिलाड़ी की खरीद का मामला केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक संदर्भों से भी जुड़ गया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों को समझे बिना इस विवाद को पूरी तरह समझना कठिन है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट लंबे समय से राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएँ भी लगभग समाप्त हो गईं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दोनों टीमें आमने-सामने खेलती रही हैं और इन मुकाबलों में खेल के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी तीव्र रूप में दिखाई देती है। हाल के वर्षों में कुछ मैचों के बाद खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हाथ मिलाने की रस्म को लेकर भी चर्चा हुई। उदाहरण के तौर पर एक मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के बीच हाथ न मिलाने की घटना मीडिया में चर्चा का विषय बनी। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग रखना हमेशा संभव नहीं होता, विशेषकर तब जब दोनों देशों के संबंध पहले से ही संवेदनशील हों। इस विवाद को आधुनिक फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले एक दशक में क्रिकेट का स्वरूप काफी बदल गया है। आईपीएल,द हंड्रेड और अन्य टी-20 लीगों ने क्रिकेट को एक वैश्विक व्यावसायिक उद्योग का रूप दे दिया है। इन लीगों में खिलाड़ी विभिन्न देशों की टीमों के लिए खेलते हैं और टीम मालिक भी अलग-अलग देशों से आते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का चयन अक्सर पूरी तरह पेशेवर मानकों के आधार पर किया जाता है। टीमों का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धी संयोजन तैयार करना होता है, न कि राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर निर्णय लेना। सनराइजर्स लीड्स का निर्णय भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्रिकेट के तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो अबरार अहमद का चयन पूरी तरह तार्किक भी माना जा सकता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

CMYK

ई-रिक्शा एजेंसी में भीषण आग

लाखों का सामान जलकर खाक

संजय पार्क के पास मयूरी ई-रिक्शा एजेंसी में दोपहर में लगी आग,दमकल की तीन गाडियों ने पाया काबू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर के संजय पार्क के पास स्थित मयूरी ई-रिक्शा केन गुप्ता एजेंसी में शनिवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर ई-रिक्शा, डीजे साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर और बैटरियां जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर-रामानुजगंज मार्ग पर शहर से लगे संजय पार्क के पास मयूरी ई-रिक्शा केन गुप्ता एजेंसी संचालित है। यहां ई-रिक्शा की बिक्री के साथ डीजे साउंड सिस्टम का निर्माण कार्य भी किया जाता है।

शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शो-रूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां खड़े ई-रिक्शा,साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर तथा बैटरियां इसकी चपेट में आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगी आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए दमकल की तीन गाडियों को बुलाना पड़ा। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक शो-रूम और गोदाम में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था।

प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से आग लगी होगी। हालांकि आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। घटना स्थल अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर स्थित है। आग लगने के दौरान वहां लोगों की भीड़ लग गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर एएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग डायवर्ट कर यातायात को सुचारू कराया।

नेशनल लोक अदालत में 3700 से अधिक लंबित मामलों का हुआ निराकरण

मोटर दुर्घटना प्रकरण में 23 लाख रुपए मुआवजा देने पर हुआ समझौता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबिकापुर और सीतापुर न्यायालय में लगभग 3700 से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में 4200 से अधिक मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड के 39 और परिवार न्यायालय के 12 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एल. चरयाणी की खंडपीठ क्रमांक 1 के समक्ष मोटर दुर्घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण का भी निराकरण हुआ। इस मामले में दुर्घटना में मृतक के परिजनों ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत 74 लाख 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया था। लोक अदालत में आपसी सहमति से बीमा कंपनी द्वारा 23 लाख रुपए मुआवजा देने पर समझौता हुआ। खंडपीठ ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि यह प्रकरण केवल 4 माह 11 दिन में सुलझ गया, जिससे मृतक की दो वर्षीय पुत्री और वृद्ध माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

पुराने मामलों का भी हुआ निराकरण

द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश तिवारी की खंडपीठ क्रमांक 4 में करीब पांच वर्ष से लंबित मोटर दुर्घटना प्रकरण का आपसी समझौते से समाधान किया गया। इसी तरह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पल्लव रघुवंशी की खंडपीठ क्रमांक 6 तथा न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना भगत की खंडपीठ क्रमांक 9 में 5 से 8 वर्ष से लंबित चेक अनादरण के मामलों का भी सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। न्यायालय प्रशासन के अनुसार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पुराने मामलों का त्वरित समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कॉर्पियो में 14 किलो गांजा के साथ नाबालिग पकड़ा गया

बांसबाड़ी के पास ग्राहक तलाशते मिले तस्कर पुलिस को देखते ही चार आरोपी दीवार फांदकर फरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है। वह अपने चार साथियों के साथ स्कॉर्पियो वाहन में 14 किलो गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस को देखते ही चार आरोपी मौके से भाग निकले, जबकि एक नाबालिग को पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बांसबाड़ी के पास स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 30 एफ 8689 में चार से पांच युवक गांजा रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वाहन में सवार युवक स्कॉर्पियो से उतरकर बांसबाड़ी की बाउंड्रीवॉल फांदकर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर 14 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे के साथ स्कॉर्पियो वाहन और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।

लैलूंगा से खरीदकर लाए थे गांजा

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ रायगढ़ जिले के लैलूंगा से गांजा खरीदकर लाया था। अंबिकापुर में इसे छोटी-छोटी पुडिया बनाकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 04 गुम इंसान किये गए बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा गुम इंसान संबंधी रिपोर्ट पर लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे दिनांक 07/02/26 कों प्रार्थी थाना कोतवाली अंबिकापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 05/02/26 कों प्रार्थी की माँ घर से कही चल गयी है, जिसका आस पड़ोस एवं रिश्तेदारो मे पत्ता तलाश किया गया जो नहीं मिल रही है, पुलिस टीम द्वारा महिला के मामले मे संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला गुम इंसान कों सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया हैं,महिला गुम इंसान घर से जाने के बाद अपने परिजनों के पास थी जिसे दस्तायाब किया गया हैं, थाना कोतवाली के दूसरे प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 03/12/25 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 29/11/25 कों प्रार्थी की पत्नी घर से बिना बताये कही चली गई हैं, आस पास खोजने से नही मिल रही हैं, पुलिस टीम द्वारा महिला के मामले मे संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला गुम इंसान कों सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया हैं, महिला गुम इंसान घर से जाने के बाद अपने परिजनों के पास थी जिसे दस्तायाब किया गया हैं। थाना कोतवाली के तीसरे प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 03/03/26 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 02/03/26 को प्रार्थी की लड़का घर से बिना बताये कही चला गया हैं, आस पास खोजने से नही मिल रहा हैं, पुलिस टीम द्वारा गुम इंसान मामले मे संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए गुम इंसान कों सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया हैं।

दोपहिया वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार,चोरी की बाइक बरामद

जिला अस्पताल के बाहर से चुराई थी मोटरसाइकिल,पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

मणिपुर थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद वाहन की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी शिवशंकर खलखो, निवासी भावराडांड सीतापुर (हाल मुकाम गंगापुर, थाना गांधीनगर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सीएल 0190 से रिश्तेदार को खाना देने जिला अस्पताल गया था। वाहन को अस्पताल के बाहर खड़ा कर अंदर चला गया। वापस लौटने पर मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। काफी तलाश के बाद भी वाहन का पता नहीं चला। रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सांडबार पुलिया की ओर उसी मोटरसाइकिल से घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अक्षय पटेल उर्फ अक्षत (21 वर्ष) निवासी सिलसिला, चौकी रघुनाथपुर थाना लुंड्रा बताया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल जब्त कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में गांधीनगर थाना से जेल जा चुका है। कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी,सहायक उपनिरीक्षक अनिल सिंह सहित पुलिस टीम और साइबर सेल के कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।

विद्या मंदिर स्कूल का वार्षिकोत्सव संपन्न,बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर के विद्या मंदिर स्कूल का वार्षिकोत्सव शनिवार को उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी,अध्यक्षता कर रहे विद्यया मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉ. पुष्पा सोनी, उपभोक्ता आयोग के सदस्य नवनीकांत दत्ता तथा पार्षद दीपक यादव की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। छोटे बच्चों ने गीत 'दिल बहल जाता है आपके आ जाने से' पर मनमोहक प्रस्तुति दी, वहीं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत 'ये तो सच है कि भगवान है' गीत ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। विद्यालय की प्रधानपाठिका साधना कश्यप ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह विद्यालय विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। यहां ऐसे बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है, जो आर्थिक या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इस अवसर पर पूर्व छात्र मानसी गुप्ता को हाईस्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय की पूर्व छात्रा आर्या सिंह राजपूत ने किया।

ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धान का अवैध उठाव,दोषियों पर FIR दर्ज

-संवाददाता-
लखनपुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

धान खरीदी केंद्र पर फर्जी नंबर प्लेट के जरिए अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। खाद्य निरीक्षक सतपाल सिंह की सतर्कता और सैटेलाइट जांच से पर्दाफाश हुआ कि 6 फरवरी 2026 को जमगला धान खरीदी केंद्र थाना लखनपुर पर एक ट्रक ने फर्जी तरीके से नंबर प्लेट सीजी 07 BS 0366 लगाकर धान उठाया था। यह ट्रक मारुति राइस मिल, भिट्ठी कला के लिए किराए पर लगाया गया था। वाहन मालिक हैप्पी सिंह (पिता गुरुमुख सिंह,निवासी अंबिकापुर) और चालक राम मानिकपुरी (पिता स्वर्गीय बाबूलाल, उम्र 27 वर्ष, निवासी अंबिकापुर) ने मिलकर यह धोखाधड़ी की। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,अंबिकापुर की जांच में पता चला कि एक ही नंबर प्लेट पर दो अलग-अलग वाहन अवैध रूप से चल रहे थे। ट्रक को दोपहर 2 बजे लखनपुर थाने लाया गया और अभिरक्षा में लिया गया। जांच में सामने आया कि ट्रक में दो चेसिस नंबर उत्कीर्ण थे: MB1NACHDXKPHH2731 –कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, MB1NACHD1JPED0258 – असली रजिस्ट्रेशन सीजी 15 DJ 9799 (इंजन नंबर CJGP Z107131) से जुड़ा पाया गया। इससे साफ हुआ कि फर्जी नंबर प्लेट सीजी 07 BS 0366 लगाकर वाहन चलाया जा रहा था, जबकि असली नंबर सीजी 15 DJ 9799 था। कोई दस्तावेज मौके पर नहीं दिखाया गया। जिला खाद्य अधिकारी सरगुजा के निर्देश पर थाना लखनपुर में वाहन मालिक हैप्पी सिंह (निवासी गुदरी चौक, चर्च रोड, केदारपुर, अंबिकापुर) और चालक राम मानिकपुरी (निवासी हुसैनी नगर, महामाया मंदिर, कोतवाली अंबिकापुर) के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।

पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से,जिले में 2314 केंद्र बनाए गए

सरकारी के साथ निजी स्कूलों के छात्र भी होंगे शामिल,प्रश्नपत्र के साथ ही उत्तर लिखने की व्यवस्था

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब कक्षा 5 वीं और 8 वीं की केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार से जिले के विभिन्न विकासखंडों में मल्टीपरपज स्कूल से प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया, ताकि परीक्षा का संचालन व्यवस्थित और गोपनीय तरीके से किया जा सके। शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष भी कक्षा 5 वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही है। इस बार एकीकृत प्रणाली के तहत परीक्षा होगी, जिसमें सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। विभाग से संबद्ध सभी निजी स्कूलों को भी इसी व्यवस्था के तहत परीक्षा करानी होगी। जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार कक्षा 5 वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तथा कक्षा 8वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्र और अन्य सामग्री ब्लॉक स्तर से परीक्षा केंद्रों तक भेजी गई है।

जिले में 2314 परीक्षा केंद्र : सरगुजा जिले के सात विकासखंडों में कुल 2314 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1563 केंद्र कक्षा 5 वीं और 751 केंद्र कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित हैं। विकासखंडवार केंद्रों की संख्या में अंबिकापुर में 595,बतौली में 211,लखनपुर में 316, लुंड्रा में 412,मैनपाट में 229, सीतापुर में 278 तथा उदयपुर में 273 केंद्र शामिल हैं। छात्रों की संख्या की बात करें तो जिले में कक्षा 5वीं के 16,667 और कक्षा 8वीं के 13,362 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कालाबाजारी को लेकर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज आलम ने जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखकर गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने और टोल फ्री नंबर जारी करने का सुझाव दिया है। परवेज आलम गांधी ने कहा कि जिले में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसके कारण आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और समय पर गैस बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, ताकि आम नागरिक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके।

C M Y K

छात्रावास में व्यवस्था का फंदा या आत्महत्या का सच ?

सोनहत के आदिवासी छात्र की मौत ने खोल दी सिस्टम की परतें

20 दिन पहले छात्र ने मीडिया के सामने खोली थी छात्रावास की अव्यवस्थाओं की पोल

- छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर बोला छात्र...20 दिन बाद फांसी के फंदे पर मिला
- खबर छपने के बाद पहुंचे थे अधिकारी,लेकिन क्या बदली कोई व्यवस्था ?
- घर जाने की जिद कर रहा था छात्र,अनुमति नहीं मिली : सूत्र
- अधीक्षक अवकाश पर,प्रभारी व्यवस्था संभाल रहे थे : घटना के बाद पहुंचे...
- सवाल बड़ाः अव्यवस्थाओं पर बोलना क्या छात्र के लिए 'अपराध' बन गया ?
- छात्रावास में व्यवस्था नहीं,सन्नाटा...11 वीं के छात्र ने लगाई फांसी...
- अव्यवस्थाओं का खुलासा किया,फिर चुप हो गया हमेशा के लिए...
- निरीक्षण हुआ, आश्वासन मिला...लेकिन एक छात्र की जिंदगी चली गई...
- व्यवस्था पर सवाल उठाने की कीमत ? आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत...
- घर जाने की जिद,अनुमति नहीं...फिर छात्र ने लगा ली फांसी...
- अधीक्षक अवकाश पर,प्रभारी व्यवस्था...और छात्र की जिंदगी खत्म
- फाइलों में सब 'संतोषजनक',छात्रावास में एक छात्र की मौत...

-रवि सिंह-

सोनहत,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के वनांचल विकासखंड सोनहत से आई एक खबर ने न सिर्फ एक परिवार का चिराग बुझा दिया,बल्कि आदिवासी छात्रावासों की व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, यहां स्थित एक आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जितनी दुखद है,उससे कहीं अधिक चिंताजनक उसके पीछे उठ रहे सवाल हैं, सवाल सिर्फ एक छात्र की मौत का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जो अक्सर कागजों में 'सुव्यवस्थित' और जमीन पर 'भगवान भरोसे' चलता दिखाई देता है, सूत्रों के अनुसार छात्र पिछले दो दिनों से काफी गुमसुम था और बार-बार घर जाने की जिद कर रहा था, बताया जा रहा है कि उसे घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी,यदि यह बात सच साबित होती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक छात्र की मानसिक स्थिति को समझना छात्रावास प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती? यह घटना जितनी दुखद है,उससे कहीं अधिक चिंताजनक उसके पीछे उठ रहे सवाल हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक आत्महत्या की घटना नहीं रह गई है,बल्कि छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं,प्रशासनिक लापरवाही और कथित दबाव की पूरी कहानी सामने लाने लगी है।

20 दिन पहले छात्र ने बताई थी छात्रावास की सच्चाई- सूत्रों के अनुसार यह वही छात्र था जिसने लगभग 20 दिन पहले मीडिया के सामने छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकारी दी थी,उसने भोजन व्यवस्था, सुविधाओं की कमी और छात्रावास की स्थिति को लेकर कई बातें सामने रखी थीं, खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक हलचल भी हुई थी, वरिष्ठ अधिकारी छात्रावास पहुंचे थे,निरीक्षण किया गया, छात्रों से बातचीत हुई और व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन भी दिया गया,लेकिन सवाल यह है कि क्या उस निरीक्षण के दौरान समस्या को समझने की कोशिश हुई या फिर समस्या बताने वाले छात्र को ही समस्या मान लिया गया?

क्या बयान देने के कारण छात्र पर पड़ा दबाव?- सूत्रों का कहना है कि छात्र द्वारा मीडिया में बयान दिए जाने से कुछ अधिकारी नाराज थे, खबर प्रकाशित होने के बाद जब अधिकारी छात्रावास पहुंचे तो क्या उस छात्र से अलग से पूछताछ हुई? क्या उसे फटकारा गया? क्या उसे दबाव में लिया गया? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि छात्र उस घटना के बाद से मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रहा था।

छात्र दो दिनों से गुमसुम था,घर जाने की कर रहा था जिद-सूत्रों के अनुसार घटना से पहले छात्र दो दिनों से काफी चुप और परेशान दिखाई दे रहा था,बताया जाता है कि वह लगातार घर जाने की जिद कर रहा था,लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई,महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बोर्ड परीक्षा का परीक्षार्थी भी नहीं था। ऐसे में छुट्टी देने में कोई बड़ी शैक्षणिक बाधा भी नहीं थी, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उसे घर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या छात्र किसी मानसिक दबाव में था? क्या वह छात्रावास के माहौल से निकलना चाहता था?

मोबाइल फोन भी बना चर्चा का विषय-सूत्रों के अनुसार छात्र के पास छात्रावास में उसका निजी मोबाइल फोन भी था, कई छात्रावासों में मोबाइल रखने पर प्रतिबंध रहता है,ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अधीक्षक को इसकी जानकारी थी? यदि जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था कमजोर थी और यदि जानकारी थी तो नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया?

अधीक्षक अवकाश पर,प्रभारी व्यवस्था के भरोसे छात्रावास-घटना के समय छात्रावास अधीक्षक अवकाश पर बताए जा रहे हैं,सूत्रों के अनुसार छात्रावास की व्यवस्था प्रभारी के भरोसे चल रही थी और घटना के बाद ही प्रभारी मौके पर पहुंचे,जिले में कई छात्रावास इसी तरह प्रभारी व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। स्थायी अधीक्षक कहीं और पदस्थ होते हैं और काम कहीं और करते हैं।

छात्रावासों में प्रभार का खेल?-सूत्रों का कहना है कि जिले में छात्रावासों के प्रभार को लेकर भी एक अलग व्यवस्था चल रही है, चर्चा है कि कुछ अधीक्षक मनचाही जगह काम करने के लिए ऊंची बोली लगाते हैं और उसी आधार पर उन्हें छात्रावास का प्रभार मिल जाता है, यानी छात्रावास अब शिक्षा का केंद्र कम और प्रभार की बोली का मैदान ज्यादा बनते जा रहे हैं।

पदोन्नति के छह माह बाद भी मूल संस्था से दूर अधीक्षक-सूत्रों के अनुसार कई अधीक्षकों की पदोन्नति हुए लगभग छह माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी मूल संस्था में नहीं भेजा गया, स्थिति यह है कि कुछ अधीक्षक मनचाही जगहों पर काम कर रहे हैं, जबकि उनकी जगह अन्य लोग प्रभार संभाल रहे हैं, बताया जाता है कि इस व्यवस्था में दो तरफा वसूली की भी चर्चा है, एक ओर पदोन्नत अधीक्षक मनचाही जगह बने रहने के लिए भुगतान करता है और दूसरी ओर उसकी जगह काम करने वाला भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भुगतान करता है।

छात्र सुविधाओं का टोटा, अधीक्षकों की जीवनशैली अलग-जिले के छात्रावासों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है,कई छात्रावासों में भोजन,स्वच्छता,बिस्तर और पढ़ाई की मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रहती हैं, लेकिन यदि अधीक्षकों की जीवनशैली देखी जाए तो वह इन कठिनाइयों से प्रभावित होती दिखाई नहीं देती, यही कारण है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं कि छात्रावास व्यवस्था आखिर किसके लिए चल रही है,छात्रों के लिए या व्यवस्था संभालने वालों के लिए?

कार्यालय से छात्रावास तक, कमी सिर्फ छात्रों की सुविधाओं में-छात्रावास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा का अवसर देना है, छात्र दूर-दूर से आकर छात्रावासों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कार्यालय से लेकर छात्रावास तक व्यवस्था की कमी शायद ही कहीं दिखाई देती हो कमी यदि है तो केवल छात्रों की सुविधाओं में।

क्या जिम्मेदारी केवल वसूली तक सीमित है?-

सूत्रों का कहना है कि जिले में छात्रावासों से मासिक और वार्षिक वसूली की परंपरा लंबे समय से जारी है, लेकिन जब बात छात्रों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को सुधारने की आती है तो वही तत्परता दिखाई नहीं देती, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल वसूली तक सीमित है या फिर छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था करना भी उनका कर्तव्य है?

एक छात्र चला गया, लेकिन सवाल छोड़ गया-

जिस छात्र ने अपनी जान गंवाई वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत कई गंभीर सवाल छोड़ गई है, क्या अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाना उसके लिए भारी पड़ गया? क्या उसे दबाव और घुटन का सामना करना पड़ा? क्या छात्रावास व्यवस्था वास्तव में छात्रों के हित में काम कर रही है? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने छात्रावासों की बंद दीवारों के भीतर चल रही कई परतों को उजागर कर दिया है, और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने की कीमत एक छात्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी?

सहायक आयुक्त पांच घंटे बाद पहुंचीं

सूत्रों के अनुसार छात्रावास की जिला स्तरीय जिम्मेदार अधिकारी सहायक आयुक्त घटना के लगभग पांच घंटे बाद मौके पर पहुंचीं, इतनी गंभीर घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी का देर से पहुंचना भी कई सवाल खड़े कर रहा है,यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि कई बार जिम्मेदारी कार्यालय की फाइलों तक सीमित रह जाती है।

आस्था पर प्रहार करने वाले 'घंटा चोर' चढ़े पुलिस के हत्थे...सोनहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सोनहत के शिव मंदिर और झरिया मंदिर से हुई थी पीतल के घंटों की चोरी

-संवाददाता-
सोनहत,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

मंदिरों की शांति और श्रद्धा को निशाना बनाने वाले शातिर चोरों के मंसूबों पर आखिरकार सोनहत पुलिस ने पानी फेर दिया है,क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिर और झरिया स्थित मंदिर से घंटों की चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने न केवल सोनहत बल्कि आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों में भी चोरी करने की बात स्वीकार की है। मंदिरों से घंटों की चोरी की घटना सामने आने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश था, लोगों ने इसे आस्था पर सीधा प्रहार बताया था और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली।

क्या था पूरा मामला-प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी चन्द्रप्रकाश साहू ने थाना सोनहत में रिपोर्ट दर्ज कराई,उन्होंने बताया कि 4 मार्च 2026 की दरमियानी रात हार्टमेंट कॉलोनी स्थित शिव मंदिर और झरिया शिव मंदिर से अज्ञात चोरों ने पीतल के भारी भरकम घंटे और घंटियां चोरी कर लीं,चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 8 हजार रुपये बताई गई है,चोरों ने मंदिर में लगे घंटों को रॉड से काटकर निकाला था। सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तो मंदिर से घंटे गायब मिले, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई, मंदिर से घंटों की चोरी को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी,क्योंकि यह केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई-मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक

रविकुमार कुर्रे,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे और उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में सोनहत पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, टीम ने आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू की, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध युवकों के बारे में जानकारी मिली, सूचना के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में पहले तो वे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे,लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर अंततः उन्होंने मंदिरों से घंटों की चोरी करना स्वीकार कर लिया।

ये हैं गिरफ्तार आरोपी पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम इस प्रकार हैं...

- **विनोद कुमार देवांगन उर्फ भोलू**
  पिता – मनीराम देवांगन
  निवासी – धुम्माडाड़
- **साहिल कुमार मानिकपुरी उर्फ सोनू**
  पिता – रामधन मानिकपुरी
  निवासी – तहसील रोड, सोनहत
- **सुमित कुमार मानिकपुरी**
  पिता – संतोष मानिकपुरी
  निवासी – सोनहत

पूछताछ में आरोपियों ने मंदिरों से घंटों की चोरी करना स्वीकार किया है।

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी- पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 20/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(ङ) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, 14 मार्च 2026 को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका- इस पूरे मामले का खुलासा करने और आरोपियों को पकड़ने में सोनहत पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कार्रवाई में विशेष रूप से थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान, उप निरीक्षक राजाराम राठिया, एएसआई हेमपाल सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र कुमार गुप्ता, आरक्षक निखलेश राजवाड़े, शंकर सुमन तिवारी, विमल जायसवाल का विशेष योगदान रहा।

CMYK

SANKALP
मॉडल से बदलेगी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

संकल्प मॉडल पर आधारित होंगी स्वास्थ्य सेवाएँ,विधानसभा में 6,976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित

जीवन की रक्षा का संकल्प,स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ा रोडमैप रखा

कैशलेस इलाज से लेकर नए मेडिकल कॉलेज तक–स्वास्थ्य बजट में कई बड़े फैसले

संकल्प मॉडल से मजबूत होगा स्वास्थ्य तंत्र,कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

रायपुर में बनेगी मध्य भारत की सबसे बड़ी खाद्य-औषधि प्रयोगशाला,स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया विस्तार

प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र और 300 एम्बुलेंसः स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की घोषणा

स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी नई ताकत, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और छात्रावास निर्माण का बड़ा बजट

-रवि सिंह-

रायपुर/एमसीबी,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6 हजार 976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित हो गई हैं, विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, उन्होंने कहा, मैं जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आया हूँ, इस प्रदेश का हर जन स्वस्थ रहे,यही सरकार का उद्देश्य है, उन्होंने बताया कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सङ्कल्प मॉडल के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुधार किया जाएगा।

बिलासपुर में बनेगा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट

प्रदेश के कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, इससे मरीजों को इलाज के लिए अन्य राज्यों या बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसके अलावा रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा, जिससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नए अस्पताल और आधुनिक एम्बुलेंस

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए अस्पतालों और सुविधाओं की भी घोषणा की गई है,अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे,रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय बनाया जाएगा,चिरमिरी में नया जिला अस्पताल स्थापित किया जाएगा,इसके साथ ही राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी,70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस, नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी।

रायपुर में बनेगी मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला

मंत्री ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी,इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,इस प्रयोगशाला के बनने से खाद्य और औषधियों की जांच के लिए दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा विस्तार

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है, प्रदेश में दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, इन महाविद्यालयों के लिए 1,240 नए पद,संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पद स्वीकृत किए गए हैं, इसके अलावा रायपुर,दुर्ग,राजनांदगांव,अंबिकापुर और जगदलपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

आयुष सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

आयुष विभाग के लिए बजट में 544 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसके तहत 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक, 692 आयुष औषधालयों का उन्नयन किया जाएगा, रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में छात्रावास और सेमिनार हॉल का निर्माण भी किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए CG-ACE योजना

पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए CG-ACE(छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन) योजना शुरू की जाएगी,इसके अंतर्गत उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा,इसके लिए बजट में 9 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में हुई व्यापक चर्चा

अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कई विधायकों ने अपने विचार रखे,चर्चा में धर्मजीत सिंह,दलेश्वर साहू,ईश्वर साहू, प्रणव मरपच्ची,आशाराम नेताम,प्रमोद मिंज,अनुज शर्मा,पुन्नूलाल मोहले, राघवेन्द्र सिंह,कुंवर सिंह निषाद,लखेश्वर बघेल,भोलाराम साहू,दिपेश साहू, प्रेमचंद पटेल, विनायक गोयल, रोहित साहू,रामकुमार यादव,व्यास कश्यप, सुशांत शुक्ला,संगीता सिन्हा,उद्धेश्वरी पैकरा,सावित्री मंडावी,उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम और यशोदा वर्मा सहित कई विधायक शामिल रहे।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर जोर

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इसके तहत,प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे,आम नागरिकों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गंभीर बीमारियों के इलाज को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है।

रायपुर में बनेगा अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत का अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है, यह संस्थान प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय हृदय रोग उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही सत्य साई संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बाल हृदय रोग उपचार सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई योजनाएं...

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए 251 करोड़ 68 लाख रुपये का बजट रखा गया है, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू की जाएगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी, बिलासपुर में 500 सीटों वाला कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा, इसके अलावा रायपुर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ और जशपुर में छात्रावासों का निर्माण भी कराया जाएगा।

इस मॉडल में शामिल हैं...

S-Strengthened Institutions **(स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाना)**

A Academic E&cellence **(उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा)**

N Ne&t Generation Research **(नवीन शोध एवं अनुसंधान)**

K Knowledge & Clinical Competency **(चिकित्सकीय दक्षता और ज्ञान)**

A Advanced Medical Facilities **(आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं)**

L Life Saving Infrastructure **(जीवन रक्षक अधोसंरचना)**

P Professional & Transparent Governance **(पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रबंधन) उन्होंने कहा कि इस मॉडल के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।**

SANKALP मॉडल से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को SANKALP मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दवंगत आरक्षक के परिवार को मिली 1 करोड़ की सहायता राशि

ड्यूटी पर जाते समय सड़क दुर्घटना में हुआ था निधन,पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिली आर्थिक मदद

-संवाददाता-

सूरजपुर,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)। ड्यूटी पर जाते समय सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए सूरजपुर जिले के आरक्षक मसत राम पैंकरा के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, यह राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत दी गई है।

डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर अविनाश पाणिग्रही ने दिवंगत आरक्षक के गृहग्राम चकेरी (शर्मा), थाना उदयपुर, जिला सरगुजा पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी कुसुम सिंह को 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा, इस दौरान अधिकारियों ने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी।

ड्यूटी पर जाते समय हुआ था हादसा

आरक्षक मसत राम पैंकरा सूरजपुर जिले में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर के गनमैन के रूप में कार्यरत थे, 17 सितंबर 2025 को ड्यूटी पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन

हो गया था। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई थी और विभाग ने दिवंगत आरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता

13 मार्च 2026 को डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर बैंक अधिकारियों के साथ दिवंगत आरक्षक के गांव पहुंचे और उनकी पत्नी कुसुम सिंह तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा की ओर से 1 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया, यह आर्थिक सहायता पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

परिवार ने जताया आभार

दिवंगत आरक्षक की धर्मपत्नी और अन्य परिजनों ने आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस विभाग और बैंक प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया, परिजनों का कहना है कि इस सहायता से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा और भविष्य की जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलेगी।

योजना का उद्देश्य

पुलिस सैलरी पैकेज योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सके, ताकि परिवार आत्मनिर्भर बन सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके, इस अवसर पर एसबीआई के डिप्टी मैनेजर प्रेमशंकर सिंह, दिवंगत आरक्षक के पिता बीर सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्य

कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

Email. ID - ddvssura.cg@nic.in

// सूचना //

प्रदेश में पशु पालकों को सस्ती और अच्छी गुणवत्त वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के सहयोग से सूरजपुर जिले के सभी विकासखण्ड में एक पशु औषधी विक्रय केंद्र खोला जाना है पशु औषधी विक्रय केंद्र के संचालन संबंधित आवश्यक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु भारत सरकार के विभागीय वेब साईट www.dahd.gov.in के मुख्य मेनू में "Pashu Aushdhi"अंतर्गत आवेदन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

Date: 11-03-2026

Nripendra Singh
उपचालक पशु चिकित्सा सेवायें
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

जी नंबर-252607153/3

बड़े पुत्र को मिली अनुकंपा नियुक्ति

दिवंगत आरक्षक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र गणेश प्रसाद को अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में नव आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है, इससे परिवार को एक स्थायी सहारा भी मिला है।

नाम परिवर्तन

मैं प्रियांशी यादव पिता भैयालाल यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 33, बाबूपारा, जेल रोड, थाना व तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) । यह कि मेरा नाम प्रियांशी यादव (Priyanshi Yadav) है, जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन क्रमांक 014142011000220 में एवं अन्य सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जो सही एवं सत्य है। मेरे आधार कार्ड क्रमांक 7894 2349 1 6302 में मेरा नाम अंग्रेजी अक्षरों Priyashi Yadav दर्ज कर दिया गया है। मेरा उक्त दोनों नाम प्रियांशी यादव (Priyanshi Yadav) एवं Priyashi Yadav महिला का नाम मेरे स्वयं का नाम है। मेरे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार मुझे प्रियांशी यादव (Priyanshi Yadav) नाम से जाना एवं पहचाना जावे, जिस हेतु मैं अपने नाम की पुष्टि के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है

शपथकर्ता
पियांशी यादव

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) /सक्षम प्राधिकारी सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क0 .../अ-2/2025-26

ईश्तहार

एतद्वारा आम ग्रामीण जन मानपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती फातमा खातून पति श्री मो. जमाल, जाति जुलाह, निवासी ग्राम मानपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा उनके स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम मानपुर, प.ह.न. 12, रा.नि.मं. सूरजपुर, तहसील सूरजपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 314 / 10 रकबा 0.012 हे. कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तन किये जाने का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 16/03/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 02-03-22026 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

विशेष कर्त्तव्याधिकारी
(रा0) भूमि व्यपवर्तन
सूरजपुर,छ0ग0
सील

न्यायायात तहसीलदार लखनपुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

लखनपुर,दिनॉक 9-3.2026

प्रति,
समस्त ग्रामवासी
ग्राम- भरतपुर
तहसील- लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक लगन साय आ0 देवराम निवासी भरतपुर तहसील लखनपुर के द्वारा अपने पुत्र स्व0 ओम नारायण की मृत्यु दिनांक 14/09/2009 को हो जाने से (जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म - मृत्यु पत्र - रिज0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत् मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर दनॉक 23/3/26 को सुनवाई की जानी है।

आवेदक/ आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी तिथी 23-3-26 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनॉक के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

तहसीलदार
लखनपुर,सरगुजा (छ.ग.)
सील

बनते ही उखड़ने लगी सड़कें

खड़गवां में लोक निर्माण विभाग की सड़कें चढ़ीं भ्रष्टाचार की भेंट

बनते ही उखड़ गई सड़क! खड़गवां में पीडब्ल्यूडी की सड़कें चढ़ीं भ्रष्टाचार की भेंट

चार दिन में दम तोड़ गई सड़क : लोक निर्माण विभाग के काम पर उठे बड़े सवाल

डामर नहीं धूल बिछी थी क्या? ग्रामीण उंगलियों से उखाड़ रहे सड़क

ठेकेदारों की मनमानी, अधिकारियों की खामोशी.... खड़गवां की सड़कें बनी भ्रष्टाचार की सड़क

सड़क बनी या मज़ाक? बनते ही उखड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क, जनता में आक्रोश
करोड़ों का विकास या घटिया निर्माण? खड़गवां की सड़कें बनी भ्रष्टाचार की मिसाल
मिट्टी पर डामर बिछा दिया! खड़गवां में सड़क निर्माण में नियमों की धज्जियां

-संवाददाता-
एमसीबी/खड़गवां,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन के बड़े-बड़े दावों के बीच एमसीबी जिले के खड़गवां विकासखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बनवाई गई सड़कें बनते ही उखड़ने लगी हैं और निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि ग्रामीण अपने हाथों से ही डामर उखाड़कर दिखा रहे हैं, यह मामला खड़गवां मुख्यालय के उन मार्गों से जुड़ा है जहां हाल ही में सड़क निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण पूरा होते ही सड़क की परत उखड़ने लगी, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन सड़कों को वर्षों तक टिकना चाहिए था,वे कुछ ही दिनों में अपनी हालत बयां करने लगी हैं।

बता दे की खड़गवां में सामने आया यह मामला केवल एक सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है,यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, अब देखना यह है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में मौन बने हुए हैं, लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान अधिकारी न तो साइट पर दिखाई देते हैं और न ही शिकायत करने पर फोन उठाते हैं, इसका फायदा उठाकर ठेकेदार मनमाने तरीके से काम करा रहे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि जब अधिकारी ही निगरानी नहीं करेंगे तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी।

जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में जनता के टैक्स का पैसा लगाया जाता है और ऐसे में घटिया निर्माण कार्य सीधे तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी है,लोगों का कहना है कि जिन सड़कों को वर्षों तक चलना चाहिए,वे कुछ ही दिनों में टूटने लगें तो यह गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

सरकार के दावों पर उठे सवाल

राज्य सरकार विकास और सुशासन के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन खड़गवां में सामने आया यह मामला उन दावों पर सवाल खड़ा करता है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि विकास कार्यों में इसी तरह की गुणवत्ता रहेगी तो विकास का लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा।

ग्रामीणों की मांग...

स्थानीय लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, खराब सड़क को दोबारा सही तरीके से बनाया जाए।

चार दिन में ही उखड़ने लगी सड़क

खड़गवां मुख्यालय में कूडाकूपारा से करवा मार्ग तक तथा आधीवार से लोहापारा तक सड़क निर्माण का कार्य कराया गया। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के महज चार दिन बाद ही सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी,स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया,सड़क की स्थिति देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में मानकों का पालन नहीं किया गया।

ग्रामीण उखाड़ रहे हैं डामर

सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब बताई जा रही है कि ग्रामीण अपने हाथों से ही सड़क का डामर उखाड़कर दिखा रहे हैं, लोगों का कहना है कि सड़क पर डामर की मोटाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है और मिश्रण भी सही तरीके से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सड़क की ऊपरी परत जल्द ही टूटकर अलग होने लगी है।

तकनीकी मानकों की अनदेखी

सड़क निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहले मिट्टी की पूरी सफाई की जाती है, उसके बाद बेस तैयार किया जाता है और फिर रोलर से अच्छी तरह रोलिंग की जाती है,इसके बाद ही डामरीकरण का कार्य किया जाता है,लेकिन आरोप है कि इस सड़क निर्माण में इन सभी तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई, बताया जा रहा है कि सड़क पर पड़ी मिट्टी को ठीक से साफ किए बिना ही सीधे डामर बिछा दिया गया, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में बेस तैयार नहीं किया जाता और सीधे डामर डाल दिया जाता है तो सड़क ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती।

ठेकेदार और अधिकारियों की 'सेटिंग' के आरोप- जब ग्रामीणों ने सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर विरोध जताया तो कथित तौर पर निर्माण कार्य में लगे लोगों ने कहा कि सब कुछ सेटिंग से चल रहा है,जो करना है कर लो,इस कथन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में सब कुछ ठीक होता तो इस तरह की बातें सामने नहीं आतीं।

सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया- इस निर्माण कार्य में एक और गंभीर अनियमितता सामने आई है, सड़क निर्माण स्थल पर कहीं भी सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे यह पता चल सके कि सड़क का निर्माण किस योजना के तहत हो रहा है, निर्माण की लागत कितनी है, ठेकेदार कौन है, कार्य की अवधि क्या है, सूचना बोर्ड न लगाना भी निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

डीलिस्टिंग की मांग को लेकर दिल्ली में 24 मई को होगा शक्ति प्रदर्शनः संत सिंह

-संवाददाता-
सूरजपुर,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में शनिवार को सूरजपुर स्थित अटलकुंज भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न ग्रामों से बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जनजाति समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आगामी 24 मई को दिल्ली में होने वाले शक्ति प्रदर्शन की जानकारी दी।

कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारियों ने जनजाति समाज को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जनजातियों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर गंभीर स्थिति बनी हुई है, उनका कहना था कि धर्मांतरण कर चुके लोग भी जनजातियों के लिए निर्धारित अधिकारों और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे वास्तविक जनजाति समाज के हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अब समाज को जागरूक और संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा।

24 मई को दिल्ली में होगा जनजातियों का शक्ति प्रदर्शन

कार्यक्रम में जिला संयोजक संत सिंह ने कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आगामी 24 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के जनजाति समाज का विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में जनजाति समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है, उन्होंने बताया कि इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग की जाएगी कि जो लोग अपने मूल जनजातीय धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपना चुके हैं,उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए, उन्होंने इसे डीलिस्टिंग की मांग बताते हुए कहा कि इससे वास्तविक जनजाति समाज के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

जिले में चल रही तैयारी

दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले भर में व्यापक तैयारी की जा रही है, जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विकासखंडों में कार्यशालाओं का आयोजन कर जनजाति समाज को एकजुट किया जा रहा है,विकासखंड सूरजपुर में आयोजित कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों से कहा गया कि वे अपने-अपने गांव और क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर समाज के लोगों को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इस कार्यक्रम

28 लाख जनजातियों के जुटने का दावा

कार्यशाला में बताया गया कि 24 मई को दिल्ली में आयोजित होने वाली महागर्जना रैली में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 28 लाख से अधिक जनजाति समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है, पदाधिकारियों का कहना था कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम जनजाति समाज की एकजुटता और अधिकारों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा।

जनजाति समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा...

जिला संयोजक संत सिंह ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जनजाति समाज अपने अधिकारों को लेकर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उनका कहना था कि कई मामलों में जनजातियों के लिए बनाई गई योजनाओं और सुविधाओं का लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, इस स्थिति को सुधारने के लिए डीलिस्टिंग की मांग को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है।

बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित...

दिल्ली में आयोजित होने वाली महागर्जना रैली में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में जनजाति सुरक्षा मंच के कई पदाधिकारी और समाज के लोग उपस्थित रहे,कार्यक्रम में जिला सहसंयोजक कामता प्रसाद सिंह, देवेंद्र सिंह (विकासखंड संयोजक), गोपाल राम (जिला संगठन मंत्री),जयंती भगत,शशि किरण खेस,आमवती नेताम,स्वाति सिंह (जनपद अध्यक्ष सूरजपुर),रामस्वरूप सिंह, सतबीर सिंह,कुंवर साय सिंह,जीतराम मिंज,दुर्गा यादव, अनेश टोप्पो,मनोज सिंह, मोहर साय सिंह,सुरेश सिरदार,निकुंज सिरदार,जय भारती सिंह सहित बड़ी संख्या में जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारी,सरपंचगण और समाज के लोग मौजूद रहे,कार्यक्रम के अंत में समाज के लोगों से अपील की गई कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर इस आंदोलन को मजबूत करें और 24 मई को दिल्ली में आयोजित शक्ति प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों।

ठाकुर अजय सिंह हाईस्कूल में वार्षिक उत्सव व विदाई समारोह का भव्य आयोजन, 33 मेधावी विद्यार्थियों सहित पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान

-संवाददाता-
कोरिया,14 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

स्थानीय ठाकुर अजय सिंह हाईस्कूल में वर्ष 2026 का वार्षिक उत्सव सह विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, पूर्व विद्यार्थियों तथा शिक्षा समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिसर उत्सव के माहौल में सराबोर रहा और विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के आगमन और उनके पुष्पगुच्छ से स्वागत के साथ हुई। इसके पश्चात मां शारदे की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा-अर्चना की गई। समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत 'अरपा पैरी के धार' के सामूहिक गायन से वातावरण में देशभक्ति और क्षेत्रीय गौरव की भावना का संचार हुआ। विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय एम.आर. ठाकुर को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।

वक्ताओं ने साझा किए विचार

अजय शिक्षा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ठाकुर और विद्यालय की प्राचार्या पार्वती यादव ने अपने संबोधन में विद्यालय की उपलब्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यालय का संचालन अजय शिक्षा समिति के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है और इसका उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक और बौद्धिक वातावरण प्रदान करना है।

इनका रहा विशेष योगदान

कार्यक्रम के सफल आयोजन में व्यवस्थापक मनीष कुमार सिंह, प्राचार्या पार्वती यादव, दीपा सिंह, सुनीता ठाकुर, बबीता सिंह, रानू गुप्ता, महेंद्र राजवाड़े, प्रीति पैकरा, स्नेहा पैकरा, रेशमी राजवाड़े, आर्ची गुप्ता और खुशी शेख का उल्लेखनीय योगदान रहा, कार्यक्रम का संचालन संवर्त कुमार 'रूप' ने किया, जबकि सह संचालन स्नेहा पैकरा और खुशी शेख ने किया, समारोह के अंत में सभी विद्यार्थियों और उपस्थित अतिथियों ने शिक्षा और संगठन की मजबूती के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनमें नृत्य, गीत और समूह प्रस्तुतियां शामिल थीं, इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया और उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

शिक्षा समिति और शिक्षकों का सम्मान

समारोह के दौरान अजय शिक्षा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ठाकुर सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों और शिक्षकों को विद्यालय के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।

33 मेधावी छात्र-छात्राओं को मिला सम्मान

कार्यक्रम में पिछले वर्ष प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले 33 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, इनमें प्रमुख रूप से आयुष राजवाड़े, उत्कर्ष ठाकुर, ममता राजवाड़े, दिव्या राजवाड़े, रौनक सिंह, खुशबू यादव, आदित्य राजवाड़े, सुनैना बखला, पंकज कुमार राजवाड़े, प्रत्युषा शर्मा, आकाश यादव, रितेश कुमार, रुस्तम राजवाड़े, प्रतीक राजवाड़े, प्राची यादव, आंचल यादव, नैतिक सिंह, गुलशन राजवाड़े, स्नेहा यादव, लक्ष्य कुमार साहू, प्रियांशु यादव, सोनू सिंह, कृष्णा, स्वरा रजक, आयुष कुमार, गरिमा सिंह, निष्ठा सिंह, राशि गोयन, उज्ज्वल, काम्या राजवाड़े, साम्या खातून, आकांक्षा और तुलसी राजवाड़े शामिल रहे।

पूर्व विद्यार्थियों का भी हुआ सम्मान

विद्यालय को गौरवान्वित करने वाले 6 पूर्व विद्यार्थियों को भी इस अवसर पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इनमें तरुणी भार्गव (शिक्षिका), शशि कुमार मांझी (मोनू, पूर्व एल्डरमैन नगर पालिका), चंदन ढीमर (व्यवसायी) और आशा भगत (पटवारी, राजस्व विभाग बैकुंठपुर) सहित अन्य पूर्व छात्र शामिल रहे।

10 वीं के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई...

समारोह के दौरान कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिव्या, खुशबू, महिमा, रौनक, अनुकल और प्रिंशु को गुलाब का फूल और उपहार देकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई।

CMYK

पति को मेरे सेट पर आना बोरिंग लगता है,वो और मैं काम के लिए एक-दूसरे की इजाजत नहीं लेते : तापसी पन्नू

तापसी पन्नू ने अपने करियर की शुरुआत भले साउथ की फिल्मों से की मगर बहुत जल्द ही बेबी और पिंक जैसी फिल्में करके उन्होंने जता दिया कि सिनेमा को लेकर उनकी चॉइस अर्थपूर्ण है। आगे चलकर उन्होंने नाम शबाना,सांड की आंख, मनमर्जियां, थप्पड़ जैसी कई फिल्मों में महिला मुद्दों को मुखर किया।

आपने अपने सिनेमा के जरिए लड़कियों के कन्सेंट, वुमन एम्पावरमेंट,घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसे कई मुद्दों को छुआ है,अब ऐसा कौन-सा मुद्दा है,जिसे आप अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं?

ईमानदारी से कहूं तो ऐसा कोई खास मुद्दा मेरे जहन में फिलहाल है नहीं। मेरे पास दो-तीन स्क्रिप्ट हैं,जो किसी धारणा को डायरेक्टली और किसी को इनडायरेक्टली इंगित करती हैं। हमेशा से कहानियों एक नाता सीख से रहा है। बचपन से यही सीखा है,तो तो मेरी एंटरटेनमेंट से भी यही अपेक्षा होती है। हालांकि कई बार सिनेमा महज मनोरंजन के लिए भी बनाया जाता है और मुझे लगता है,वो भी देखा जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि अस्सी चल जाए और मैं अपने मिजाज का सिनेमा बना सकूं।

आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में हीरोइन्स आसानी से रीप्लेस हो जाती हैं?

जी हां बिलकुल हो जाती हैं। मुझे लगता है हीरोइन ही क्यों? कोई भी कलाकार रिप्लेस किया जा सकता है। हमें कभी भी खुद को इतना बड़ा नहीं मानना चाहिए कि हम रिप्लेस नहीं हो सकते। आसानी और मुश्किल का जो भेद है, उसे बनाए रखना चाहिए। आपने अगर अपनी मजबूत जगह बना ली है, तो आपको हिलाना मुश्किल हो सकता है,वो हम एक्टर्स के हाथ में होता है कि हम किस रंग के कलाकारों के साथ खड़े होते हैं,हम किन चरित्रों के लिए जाने जाते हैं।

एक निर्माता बनने पर आपने किन चुनौतियों का सामना किया है?

मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और अभी भी कर रही हूं। ऐसा होता है न कि आपके पास ये कहानी है, तो कोई बड़ा नाम लेकर आइए। बड़े नाम के साथ बड़े खर्चे भी आते हैं,मगर जिस तरह की फिल्में मैं चुनती हूं, उतना उन्हें मिलता नहीं है। इतना बड़ा स्टार इस फिल्म में क्यों आएगा? क्योंकि इसकी तो छोटे बजट की फिल्म है। ये सब उन्हीं कलाकारों को सूट करती हैं, जिनसे आप बड़े स्टार वाली उम्मीदें लेकर नहीं घुसते।

आपके पति (अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियास बो) एक अलग क्षेत्र से हैं,आप लोग एक -दूसरे के प्रोफेशन में कितनी रुचि लेते हैं?

हम जब इंसान के रूप में एक-दूसरे में रुचि लेते हैं, तो हमारा प्रोफेशन तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है,तो हम उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं,मगर इतनी भी नहीं कि हम दिन-रात उसी की चर्चा करें। मैं उनके मैच देखती हूं,मुझे जानकारी होती है कि वे किसे कोच कर रहे हैं। अब वो फुलटाइम प्लेयर नहीं हैं। वे कई बार मेरे साथ आउटडोर लोकेशन पर होते हैं,हालांकि वो सेट पर कभी नहीं आते। उन्हें सेट पर आना बहुत बोरिंग लगता है, मगर मेरे साथ समय बिताने के लिए वे मेरे साथ होते हैं। हम दोनों का एक बेहद अच्छा तरीका है, एक-दूसरे के साथ ग्रो करने का। हमें अपने प्रोफेशन को लेकर एक-दूसरे से परमिशन नहीं मांगनी होती। अपने काम के फैसले हमारे अपने होते हैं, मगर अहम उन फैसलों का साथ देते हैं। अच्छा ही है कि हम एक ही क्षेत्र से नहीं हैं।

विजय-तृषा की निजी जिंदगी में दखल देना सही नहीं : विक्रांत भट्ट

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की उनकी पत्नी संगिता सोनालिंगम के साथ तलाक की खबरों और अभिनेत्री तृषा क्रष्नन के साथ कथित अफेयर की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। हाल ही में एक शादी समारोह में विजय और तृषा को साथ देखे जाने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इसी बीच फिल्ममेकर विक्रांत भट्ट ने एक लंबी पोस्ट लिखकर दोनों का समर्थन किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विक्रम भट्ट ने अपनी पोस्ट में कहा कि विजय और तृषा की निजी जिंदगी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उस पर वह अपनी राय रखना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट पर फैल रही अफवाहें सच हैं या नहीं, लेकिन अगर उनमें कुछ सच्चाई भी है, तो भी लोगों को किसी की निजी जिंदगी पर फैसला सुनाने से बचना चाहिए। विक्रम ने अपने हाल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन में कुछ परिस्थितियां इंसान को आजादी की अहमियत समझा देती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कैद वह होती है,जब उसकी खुशी और उसकी आत्मा किसी ऐसे रिश्ते में बंध जाए, जिसका समय खत्म हो चुका हो। फिल्ममेकर ने आगे कहा कि कई बार समाज लोगों को ऐसे रिश्तों में बने रहने के लिए मजबूर करता है, जहां वे खुश नहीं होते। उनके अनुसार इंसान का दिल स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाता है,जहां उसे खुशी मिलती है। विक्रम भट्ट ने लिखा कि लोग खुशी पाने के लिए रिश्तों में आते हैं और अगर वही खुशी खत्म हो जाए तो अलग होने का फैसला भी ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी रिश्ते से सम्मान के साथ बाहर निकलना गलत नहीं है। पोस्ट में विक्रम ने विजय और तृषा के बारे में कहा कि उन्हें उन दोनों में एक तरह की सच्चाई दिखाई देती है। उनके अनुसार किसी भावना या रिश्ते को छिपाने की बजाय उसे स्वीकार करने में भी एक गरिमा होती है। उन्होंने साफ कहा कि कलाकारों की फिल्में और काम दर्शकों के लिए होते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी पर समाज का अधिकार नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि विजय की पत्नी संगीता ने तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और याचिका में कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी जिक्र किया गया है।

19 साल का था,ऑटो में पहली बार लबों से लब टकराए,मां कहती है- शादी कर लो : सिद्धांत चतुर्वेदी

यूपी के बलिया में पैदा हुए सिद्धांत चतुर्वेदी की सफलता ने छोटे शहरों में रहकर बड़े सपने संजोने वालों के हौसलों को नई उड़ान दी है। वह अपनी भूमिकाओं को अपने खास अंदाज में निभाने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे डेब्यू फिल्म 'गली बॉय' हो,या फिर 'गहराइयां', 'खो गए हम कहां', और 'धड़क 2', सिद्धांत को हर किरदार में दर्शकों का खूब प्यार मिला। इन दिनों वह 'दो दीवाने सहर में' फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। यह एक नए जमाने की देसी लव स्टोरी है। सिद्धांत अपने बचपन की मोहब्बत का एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं, जहां उन्हें प्यार भी हुआ और दिल भी टूटा। बात शादी की चली, तो एक्टर ने बताया कि उनके पैरेंट्स इसके लिए कहते रहते हैं। पहला प्यार, आम तौर पर एक तरह का आकर्षण ही होता है। खासकर, यदि वह बाली उमर में हो। अपने ऐसे ही इनफैचुएशन के बारे में सिद्धांत कहते हैं, 'मैं उस वक्त चौथी क्लास में था। एक लड़की दिल्ली से ट्रांसफर होकर हमारे शहर आई थी। वो मेरे बगल में ही बैठती थी। बला की खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही इनफैचुएट हो गया था। मगर वो सालभर में चली गई थी। उसने जाते समय कहा था कि वो वापस आएगी। मगर वो कभी वापस नहीं आई, तो हमारा मेरा वो बचपन एक इश्क अधूरा रह गया।'

सिद्धांत चतुर्वेदी बोले...मेरा भी दिल टूटा है...

हर रिश्ता जीवन में कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। सिद्धांत अपनी रिलेशनशिप के फेल्योर पर कहते हैं, 'मेरा भी दिल टूटा है,मगर कमाल की बात ये है कि कई बार जब आप उस रिश्ते में होते हैं,तो आपको लगता है कि वो हमेशा के लिए रहने वाला है। आप उसी हिसाब से अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, मगर जब वो चीजें टूटती हैं,तो बहुत मुश्किल होता है,उस चीज से उबरना। मैंने सीखा कि जिंदगी कई बार आपको आश्चर्यचकित करती है। 'लाइफ ऑफ पाई' फिल्म में एक सीन था,जब लड़का और टाइगर समंदर के किनारे पहुंचते हैं,तब टाइगर जंगल में आगे बढ़ जाता है। उस फिल्म में इरफान सर (इरफान खान) का डायलॉग था कि मुझे लगा वो टाइगर मुड़ेगा,मेरी तरफ देखेगा,जो सफर हमने तय किया है, उसकी बातें होंगी,लेकिन वो सीधा-सीधा चलता गया और कहीं न कहीं जंगल में जाकर गुम हो गया। तब मैंने समझा कि कई बार जाने देने का नाम ही जिंदगी है। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता कि वो आपके साथ जिंदगी भर के लिए रहे। कई रिश्तों को आपको छोड़ना भी पड़ता है। छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं है। लोग बदलते हैं,चीजें बदलती है और आपको उसे स्वीकार करना होता है। जो आपके लिए लड़ सके और अडिग खड़ा रह सके,वो बहुत दुर्लभ होता है,जो मैंने अपने माता-पिता में देखा है। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं।'

एक्टर बनने के बाद भी हुआ प्यार, रिजेक्ट भी हुआ हूं...

प्यार में रिजेक्शन पर सिद्धांत कहते हैं, 'प्यार के मामले में मैं कई बार नकारा गया हूं। बचपन से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। मैंने क्लासरूम में सभी के सामने लड़की को प्रपोज करके अपनी बहुत बेइज्जती करवाई है। एक्टर बनने के बाद भी रिजेक्ट हुआ हूं। असल में प्यार-मोहब्बत को लेकर मेरा अप्रोच फ्रंटल नहीं होता। मेरे मन में नकारे जाने का डर इस कदर बैठा है कि मैं सामने से पहल नहीं कर पाता। असल में बचपन में कई बार रिजेक्ट हुआ हूं। कई बार मैं पूछने से ही डर जाता हूं,पर रिजेक्ट होने का मजा अब है, जब मैं कुछ बन चुका हूं। तब लगता है कि वो मेरी पोजीशन या कलाकार होने की परवाह किए बगैर मुझसे चाहती है कि मैं उसे एक इंसान के रूप में सच्चे मर्द की तरह अप्रोच करूं। मेरे साथ यही हुआ था। उसे मेरी परवाह ही नहीं कर थी। मैं सोच रहा था मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ऐसे किसी की तलाश में हूं, जिसके लिए मेरा स्टारडम कोई मायने न रखता हो।'

19 साल की उम्र में वो पहला किश,आज भी नहीं भूला

अपनी पहली किश पर सिद्धांत चतुर्वेदी शरमा जाते हैं। फिर कहते हैं, 'मैं उस वक्त उन्नीस साल का था। उस किस को करते हुए मुझे इंद्रलोक में होने का अहसास हुआ था। मैं और वो ऑटो में थे। हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। जो मैंने फिल्मों में देखा था,वैसा मुझे असल जिंदगी में महसूस हो रहा था। उसका जन्मदिन था। मुझे उसे घर ड्रॉप करना था और वो मेरे कंधे पर सो गई थी। उस रोमांटिक शाम को मुंबई के गड्ढों ने और रोमांटिक बना दिया था। अगले दिन हम जब मिले,तो मैं बहुत शरमा गया था। हमारा पहला किस डेटिंग के एक साल बाद हुआ था। मैं कॉलेज में था। खैर उसके बाद तो ऑटो में किसिंग का सिलसिला चल निकला था। अरे,एक बार तो हमें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ भी लिया था। तब मुझे उस सिचुएशन को संभालने के लिए पहली बार रिश्वत देनी पड़ी थी।'

शादी का दबाव लड़कों पर भी होता है,मुझ पर भी है...

हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों पर शादी का दबाव ज्यादा होता है,मगर सिद्धांत इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं, 'मुझ पर भी घर से शादी का दबाव है। मेरी मम्मी तो रोजाना कहती हैं, पापा तो ऑफिस चले जाते हैं,तुम चले जाते हो शूटिंग और भाई चला जाता है कॉलेज,तो तुम शादी कर लो। मैंने कहा, मम्मी जो लड़की आएगी, वो भी तो काम पर जाएगी, तो मम्मी एक कहना है,बच्चा-वच्चा होगा, तो मैं उसे खिलाऊंगी। मैं तो हंसते हुए मम्मी से कहता हूं,सारी उम्मीदें मैं ही पूरी करूं आपकी। मैंने तो अपनी मम्मी से कह दिया है कि 6-8 साल रुकिए अभी, पर मैं उनकी सोच भी समझ सकता हूं। उन्हें लगता है कि वे बूढ़े हो गए हैं और उनके बाद मेरा क्या होगा मां कहती हैं, हमारे बाद तुम्हें कौन संभालेगा मैंने तो मां से कह दिया, अगर आपको ऐसा लगता है, तो कल से जिम जाइए, फिट रहिए, आप लोगों को अभी बहुत जीना है। मुझे सेटल करवाने की रट में मैंने तो उन दोनों का जिम लगवा दिया और उनसे साफ कह दिया कि उन्हें कुछ भी उल्टा-सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी लंबी पारी खेलनी है।'

ऐसा जीवनसाथी चाहता हूं,जिसके साथ हंसू और रोऊं

आपको जीवनसाथी के रूप में कैसी लड़की चाहिए इस पर वे फलसफे वाले अंदाज में कहते हैं,' ऐसी लड़की जिसके साथ मजा आए। जीवन में बहुत-सी दिक्कतें होती हैं। जैसे -जैसे हम उम्रदराज होंगे, जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। इससे आपको एक कंपैनियन मिल जाता है और जिंदगी जीने में आसान हो जाती है। जिनके साथ सुख-दुख बांटने में मजा आए, जिसे सोते हुए देख उसके बालों को संवारूं।'

मैं अपने मम्मी-पापा जैसी कंपैनियन शिप चाहता हूं...

सिद्धांत आगे कहते हैं, 'हाल ही में मेरे माता-पिता की एनिवर्सरी थी और मैंने उन्हें काठमांडू की ट्रिप पर भेजा। मम्मी को काठमांडू जाने की बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी मम्मी पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी की यादों को ताजा कर रही थीं कि आज हमारा तिलक हुआ था, इस दिन हम ससुराल आए थे। मम्मी की बातें सुनकर मैं सोच रहा था कि मम्मी की सबसे बड़ी पूंजी तो उनका परिवार ही है। सच कहूं, तो मैं अपने मम्मी -पापा जैसी कंपैनियन शिप चाहता हूं।'

खेल समाचार

नमन अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा...राहुल द्रविड़ और मिताली राज को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने प्रतिष्ठित नमन अवार्ड 2026 के लिए सालाना पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार के समारोह में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाएगा। यह भव्य कार्यक्रम 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा,जिसमें अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और आयु-वर्ग क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मान मिलेगा। इस वर्ष के अवॉर्ड समारोह में पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड और बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए 'कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा। यह बीसीसीआई का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं

भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मिताली राज को 'बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड फॉर विमेन' से सम्मानित किया जाएगा। 2024-25 सीजन के प्रदर्शन के आधार पर कई खिलाड़ियों को भी प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाएंगे। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष)' के लिए पॉली उमरीगर अवॉर्ड दिया जाएगा। गिल को यह सम्मान दूसरी बार मिलेगा। वहीं भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मांदना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पांचवीं बार 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला)' के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। घरेलू क्रिकेट में भी कई खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। मुंबई की युवा खिलाड़ी ईरा जादव को बल्ले से शानदार प्रदर्शन के लिए 'सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (घरेलू)' की जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं हरियाणा की स्टार बल्लेबाज शैफाली वर्मा को सीनियर महिला घरेलू एकदिवसीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। पुरुष घरेलू क्रिकेट में मुंबई के आयुष मात्रे को लिमिटेड ओवर प्रतियोगिताओं में 'सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर' के लिए लाला अमरनाथ अवॉर्ड दिया जाएगा, जबकि विदर्भ के हर्ष दुबे को रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए इसी श्रेणी का सम्मान मिलेगा। इसके अलावा मुंबई क्रिकेट एशोसिएशन को घरेलू टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन के लिए 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' का पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि इस सीजन में उसने चार ट्रॉफियां जीतने के साथ दो प्रतियोगिताओं में उपविजेता स्थान भी हासिल किया। नमन अवॉर्ड्स 2026 का एक विशेष आकर्षण उन भारतीय टीमों का सम्मान होगा जिन्होंने सभी पांच प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं। इसमें आईसीसी चैम्पियन्य ट्राफी 2025 और आईसीसी टी20 विश्वकप 2026 जीतने वाली सीनियर पुरुष टीम, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 जीतने वाली महिला टीम, आईसीसी अंडर -19 क्रिकेट वर्ल्डकप 2026 जीतने वाली पुरुष अंडर-19 टीम और आईससी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्डकप 2025 जीतने वाली महिला अंडर-19 टीम शामिल हैं।

विदेशी खिलाड़ियों से मजबूत दिख रही आरसीबी : कुंबले

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इससे पहले क्रिकेट विशेषज्ञ अलग-अलग टीमों का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बैंगलुरु की टीम का आकलन किया है।

उन्होंने कहा कि आरसीबी की ताकत उसके विदेशी खिलाड़ी हैं, जो टीम को काफी मजबूत बनाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि प्लेइंग इलेवन तय करना टीम मैनेजमेंट और कप्तान के लिए आसान नहीं होगा। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी 28 मार्च को सनराईज हैदराबाद के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कुंबले के मुताबिक आरसीबी के लिए यह बेहद जरूरी होगा कि वह अपने विदेशी खिलाड़ियों का सही संयोजन बनाए। कुंबले का मानना है कि ये दोनों खिलाड़ी निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी कर मैच को शानदार तरीके से फिनिश करने की क्षमता रखते हैं।

सौरव गांगुली की चेतावनी...बोले-2027 वनडे वर्ल्ड कप में होगी असली परीक्षा

नई दिल्ली,14 मार्च 2026। हाल ही में टीम इंडिया ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में आईसीसी टी20 विश्वकप 2026 का खिताब जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस जीत के साथ गौतम गंभीर ऐसे पहले भारतीय कोच बन गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में टीम को आईसीसी चैम्पियन ट्राफी और टी20 विश्व कप दोनों का खिताब दिलाया है। हालांकि इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने टीम को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि असली चुनौती अभी बाकी है। एक इंटरव्यू में गांगुली ने कहा कि सफेद गेंद के क्रिकेट में भारतीय टीम की असली परीक्षा 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में होगी। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा और वहां की परिस्थितियां टीम और कोच दोनों की क्षमता की कड़ी परीक्षा लेंगी। गांगुली का मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम मजबूत है और उसके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है, इसलिए

अगर टीम सही दिशा में आगे बढ़ती है तो वह इस चुनौती में भी सफल हो सकती है। गांगुली ने यह भी कहा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में सफलता मिलने के बावजूद भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की जरूरत है। उनके मुताबिक रेड बॉल क्रिकेट में टीम को विकेटों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय अपनी प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए और बेहतर पिचों पर खेलने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि घरेलू सीरीज, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबलों में केवल टर्निंग ट्रैक तैयार करने की रणनीति से बचना चाहिए। गांगुली के अनुसार अच्छे और संतुलित विकेट बेहतर क्रिकेट को जन्म देते हैं और इससे टीम का प्रदर्शन भी मजबूत होता है। उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में निरंतर सफलता के लिए यही रास्ता सबसे सही है। पूर्व कप्तान ने गौतम गंभीर के कामकाज की भी सराहना की और कहा कि वह एक सक्षम कोच हैं। गांगुली ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले भी कहा था कि गंभीर को टीम के साथ काम करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक सीमित ओवरों के क्रिकेट में गंभीर ने खुद को साबित किया है और उनके पास एक मजबूत टीम भी मौजूद है।

CMYK

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 11 जिलों में 29 गौधाम का किया शुभारंभ

गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,14 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना का शुभारंभ किया। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जिलों में 29 गौधामों का संचालन प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के ग्राम जोगीपुर में राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जोगीपुर में प्रस्तावित गौ अभ्यारण्य लगभग 184 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पूर्ण होने पर यहां एक साथ लगभग 2500 गौवंश के संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था की जा सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति,आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौधाम योजना के माध्यम से बेसहारा एवं घुमंतू गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एमओयू किया गया है। इसके तहत कई जिलों में गाय वितरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है,जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौधामों में गौवंश के लिए चारा, पानी और समुचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में शासकीय भूमि पर स्थापित सभी गौधाम अब 'सुरभि गौधाम' के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि गौधामों में पशुपालन,हरा चारा उत्पादन तथा गोबर से उपयोगी उत्पाद तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि गौधाम योजना का शुभारंभ एक पुनीत अवसर है।

उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है तथा गोधन संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, जब पूरे प्रदेश में एक साथ गौधाम योजना की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में 10-10 गौधाम चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे,जिससे गौवंश संरक्षण के साथ-साथ लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल ने कहा कि गौ माता हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सुनियोजित कार्ययोजना के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल,धरमलाल कौशिक,धर्मजीत सिंह,सुशांत शुक्ला,महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कमिश्नर बिलासपुर सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल,एसएसपी रजनेश सिंह,संचालक पशु चिकित्सा चंद्रकांत वर्मा सहित बड़ी संख्या में गौपालक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में एलपीजी की जमाखोरी पर बड़ा एक्शन,102 जगहों पर छापे,741 सिलेंडर जब्त

रायपुर,14 मार्च 2026। ईरान और अमेरिका-इजरायल संघर्ष के चलते गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। शनिवार को राज्यभर में की गई कार्रवाई के दौरान 102 अलग-अलग स्थानों से कुल 741 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार, राज्य के खाद्य विभाग की टीमों और जिला प्रशासन ने मिलकर संदिग्ध स्थानों पर अचानक निरीक्षण और छापेमारी की। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना और संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कारोबार करने वालों पर रोक लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए कुछ व्यापारी गैस की संभावित कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर कई जिलों में छापेमारी की गई।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अलग-अलग जिलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई गोदामों, दुकानों और अन्य संदिग्ध जगहों पर छापे मारे गए, जहां बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से जमा किए गए थे। बयान के मुताबिक अब तक राज्यभर में 102 स्थानों से 741 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई रायपुर में हुई, जहां अलग-अलग निरीक्षणों के दौरान 392 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। इसके बाद बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा, जहां प्रवर्तन कार्रवाई में 130 सिलेंडर बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कई वेयरहाउस, दुकानें और अन्य स्टोरेज स्थान भी खंगाले गए, जहां सिलेंडर की जमाखोरी होने की आशंका थी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी, डायवर्जन या कालाबाजारी में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं एलपीजी की संदिग्ध बिक्री या अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने कहा कि अनिश्चितता के समय में जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी करने से कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बीच, शनिवार को मुंबई में भी एलपीजी की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया। यहां वर्ली इलाके में अधिकारियों ने एक रिहायशी स्थान पर छापा मारकर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच में पता चला कि इन सिलेंडरों को कथित तौर पर अवैध रूप से जमा करके उनमें गैस भरने के बाद ब्लैक मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सिलेंडरों के साथ एक ट्रांसपोर्ट वाहन भी जब्त किया गया है। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है।

नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता

18 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद

सुकमा,14 मार्च 2026। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 226 बटालियन सीआरपीएफ की सी कंपनी ने गोमगुड़ा क्षेत्र के पोडियमपारा में एंबुश ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के एक डंप साइट का पता लगाया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से करीब 18 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की। बरामद सामान में तिरपाल,स्लीपिंग बैग, पिट्ठू,नक्शा-चार्ट और अन्य उपयोगी सामग्री शामिल हैं,जिनका इस्तेमाल नक्सली अपने ठिकानों और गतिविधियों के लिए करते थे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। सीआरपीएफ ने अपने बयान में कहा है कि क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी,ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का है लक्ष्य

बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा अब अंतिम चरण में है। 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह समाप्त करना है। सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों और पुनर्वास नीति के चलते 1300 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बस्तर अब हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है।

दुर्ग में अफीम की खेती मामला...कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड

नोटिस के जवाब में कहा-बिजली की फेंसिंग,आवारा जानवरों की वजह से नहीं कर सकी निरीक्षण

दुर्ग-भिलाई,14 मार्च 2026। दुर्ग जिले के समोदा गांव में बीजेपी नेता के खेत में अफीम की खेती पकड़ाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी विभागीय कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने निलंबित कर दिया है। इस मामले में पटवारी अनिता साहू और फसल सर्वेयर शशिकांत साहू को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि उन्होंने जिस खेत को मक्का फसल के प्रदर्शन प्लॉट के रूप में दिखाया था, वहां असल में धान की फसल लगी हुई थी।

जवाब में कहा...किसान की तबीयत खराब थी,दूसरे की फोटो अपलोड की : अपने जवाब में कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू ने बताया कि, प्रदर्शन प्लॉट किसान के बताए स्थान पर ही चुना गया था। खराब नेटवर्क के कारण फोटो सही तरह से अपलोड नहीं हो पाई थी। किसान की तबीयत खराब होने के कारण उसके प्रतिनिधि की फोटो पोर्टल पर अपलोड की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि, प्रदर्शन बोर्ड उन्हें कार्यालय से नहीं मिला था। खेत के आसपास

बिजली की फेंसिंग और आवारा पशुओं की वजह से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करना संभव नहीं हो पाया। हालांकि अधिकारियों ने इन सभी कारणों को संतोषजनक नहीं माना। प्रशासन का कहना है कि यह अपने दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन है।

प्रदर्शन प्लॉट दिखाया,लेकिन मौके पर धान की फसल मिली : जिला कृषि विभाग के अधिकारियों ने 7 मार्च को समोदा गांव में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगाए गए मक्का फसल प्रदर्शन प्लॉट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पता चला कि जिस जमीन को मक्का फसल का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया था, वहां वास्तव में मक्का की फसल नहीं थी। उस खेत में धान की फसल लगी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि कृषि मैप पोर्टल पर असली किसान की जगह किसी अन्य व्यक्ति की फोटो अपलोड की गई थी। इसके अलावा प्रदर्शन प्लॉट पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। वहीं पास में अफीम की फसल होने के बावजूद इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी गई। इन सभी बातों को गंभीर लापरवाही मानते हुए कृषि विस्तार अधिकारी से जवाब मांगा गया था।

तीन कर्मचारियों को जारी हुआ है नोटिस

प्रशासन के मुताबिक,इस मामले में तीन कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई थी। इनमें पटवारी अनिता साहू, फसल सर्वेयर शशिकांत साहू और कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू शामिल हैं। 11 मार्च को तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। एकता साहू ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन अधिकारियों को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद कलेक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फिलहाल पटवारी और सर्वेयर के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। उनके जवाब आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।

सर्वेयर और पटवारी की भूमिका भी जांच में...

जांच में यह भी सामने आया कि फसल सर्वेयर ने सितंबर 2025 में खेत का डिजिटल सर्वे किया था। उस समय उसने खसरा नंबर 309 को खाली जमीन और खसरा नंबर 310 में धान की फसल होने की जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड की थी। बाद में इन्हीं जमीनों पर अफीम की खेती मिली। नियम के मुताबिक सर्वेयर द्वारा अपलोड किए गए डेटा का मौके पर जाकर सत्यापन करना पटवारी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पटवारी ने बिना जांच के ही रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसी वजह से अफीम की खेती का मामला सामने नहीं आ सका।

ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध कबाड़ पर बड़ी कार्रवाई

6 वाहन समेत 83 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

रायगढ़,14 मार्च 2026। जिले में अवैध कबाड़ के कारोबार पर अंकुश लगाने रायगढ़ पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पूंजीपथरा और पुसौर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों से लगभग 130 टन स्क्रैप और आयरन पेललेट्स जब्त किए हैं। दोनों थानों की कार्रवाई में कुल 83 लाख 52 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर अवैध परिवहन में लिप्त 6 वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुसौर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुसौर-सरिया मार्ग पर चेकिंग के दौरान दो टाटा 1512 वाहनों को रोका गया, जिनमें करीब 19 टन लोहे का स्क्रैप परिवहन किया जा रहा था। चालकों द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दोनों वाहनों सहित स्क्रैप जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं पूंजीपथरा थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तमनार चौक और महुआ चौक तुमीडीह में घेराबंदी कर उड़ीसा की ओर से आ रहे चार भारी वाहनों को रोका, जिनमें तीन ट्रकों में आयरन पेललेट्स और एक ट्रक में करीब 25 टन स्क्रैप लोड मिला। जांच में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने सभी वाहनों और सामग्री को जब्त कर चालकों के विरुद्ध धारा 35(क), (ड) बीएनएसएस तथा 303(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की है।

कार्रवाई में 3 ट्रकों से 86 टन आयरन पेललेट्स तथा 3 वाहनों से 44 टन लोहे का स्क्रैप बरामद किया गया, जबकि जब्त किए गए 6 वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध कबाड़ और चोरी के माल के कारोबार पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

असहिष्णु भाजपा...छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार,पीएम मोदी के खिलाफ किया था पोस्ट

रायपुर,14 मार्च 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने कौशांबी से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की राजनधानी रायपुर के रहने वाले विनोद तिवारी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने कौशांबी आए हुए थे। जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महेवाघाट थाना क्षेत्र के डक शरीरा गांव से दिल्ली पुलिस ने उन्हें

अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक,विनोद तिवारी अपने पिता के पिंडदान के लिए संगम आए थे। इस दौरान वह कौशांबी के महेवाघाट थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव डक शरीरा पहुंचे थे। उन पर आरोप है कि फरवरी में विनोद ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। इधर विनोद तिवारी का कहना है कि 3 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी। जिसको लेकर दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद ने बताया कि वे गया अपने पिता का श्राद्ध करने आये हुए थे। सूचना पाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें दिल्ली लेकर जा रही है। इधर इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पोस्ट कर लिखा है कि 'असहिष्णु भाजपा। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में अपने पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने मोदीजी के खिलाफ 3 फरवरी को किए गए पोस्ट के वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है।'

साय सरकार की नशे के खिलाफ निर्णायक जंग एसओजी और एंटी नारकोटिक्स सेल का किया गठन

रायपुर,14 मार्च 2026। छत्तीसगढ़, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, प्राकृतिक संसाधनों और शांत सामाजिक जीवन के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने चिंतनीय स्थिति पैदा की है। नशीले पदार्थ केवल कानून-व्यवस्था की दृष्टि से ही समस्या नहीं हैं बल्कि यह समाज, परिवार और युवाओं के भविष्य के लिए भी गंभीर चुनौती है। इसका सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व

में राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है। राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने से साथ ही साथ प्रदेश को नशामुक्त बनाने की व्यापक रणनीति तैयार की है। साय सरकार का स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ में नशे के व्यापार के लिए कोई जगह नहीं है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब क़ानून का शिकंजा कसा जाएगा। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी आज नशे की समस्या से जूझ रहा है। तरह-तरह के मादक पदार्थों जैसे गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर,अफीम,डोडा और सिंथेटिक ड्रग्स समाज के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत से क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क सक्रिय हो रहा है। विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों और विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य में नशे के सेवन करने वालों की संख्या चिंताजनक हो सकती है।

चालानी कार्रवाई के दौरान हंगामा...पुलिस से धक्का-मुक्की करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर,14 मार्च 2026। राजधानी रायपुर में नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस के साथ विवाद और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। चालानी कार्रवाई में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया,जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत यातायात पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों और रिंग रोड पर नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में

शुक्रवार रात लगभग 8 बजे टाटीबंध चौक से सिलतरा बाईपास रिंग रोड नंबर 4 में कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान यातायात थाना टाटीबंध के प्रभारी निरीक्षक विशाल कुजूर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक संदीप मिश्रा, आरक्षक संजीत सिंह और डी. उमेश द्वारा नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान रिंग रोड नंबर 4 बायपास मार्ग पर नो-पार्किंग में खड़े एक ट्रक के खिलाफ ई-चालान बनाया जा रहा था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)